▪ RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 197 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » गुरुवार » 12-02-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जरिए कृषि क्षेत्र के लिये संकट पैदा कर रही भाजपा सरकार : अखिलेश

6 साहस और विनम्रता जीवन की सच्ची महक

7 रिंग में उतरीं फातिमा सना शेख, दिखाया फुल पावर अवतार

फर्स्ट टेक

'सोनम वांगचुक को चिकित्सकीय आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता'

नई दिल्ली। सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य के आधार पर सोनम वांगचुक को रिहा करना मुमकिन नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि वांगचुक की चिकित्सा स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की गई है और उनकी रिहाई को उचित ठहराने वाली कोई 'चिंताजनक बात' नहीं है। चिकित्सा कारणों से किसी भी प्रकार की छूट का विरोध करते हुए, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा, स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा करना संभव नहीं होगा। यह वांछनीय भी नहीं हो सकता है। हमने इस पर पूरा विचार किया है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा, हमने समय-समय पर 24 बार उनकी सेहत की जांच की है। वे स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्हें पाचन संबंधी कुछ समस्याएं थीं, उनका इलाज चल रहा है।

कांग्रेस ने असम का 'वोट बैंक की राजनीति' के लिए इस्तेमाल किया

गुवाहाटी/भाषा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर, विशेषकर असम का ''वोट बैंक की राजनीति'' के लिए इस्तेमाल किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर पर उचित ध्यान दिया है और इस क्षेत्र को देश के विकास का केंद्र बनाया है। चौहान ने कहा, दशकों तक, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर, विशेषकर असम को अपनी कुख्यात वोट बैंक की राजनीति को अंजाम देने की जगह के रूप में माना। उसके कार्यकाल के दौरान जर्जर सड़कें, खराब रेल नेटवर्क, कोई उद्योग नहीं था और कोई रोजगार सृजन नहीं था।'' उन्होंने कहा, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने कार्यभार संभाला तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और क्षेत्र की सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। चौहान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट ने विकसित भारत का पूरा खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा, ''पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 'चिकन नेक कॉरिडोर' भारत की एकता का पुल और देश की अखंडता की रीढ़ है।''

12-02-2026 सूर्यास्त 6:13 बजे | 13-02-2026 सूर्योदय 6:34 बजे

BSE	NSE
84,233.64	25,953.85
(-40.28)	(+18.70)

सोना	चांदी
16,321 रु.	274,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

हिंदी सीखिए

निज भाषाओं को सब सीखे,
बोलें पढ़ें करें सब बोध।
पर दूजे भाषा-भाषी पर,
व्यर्थ कर रहे कुछ दल क्रोध।
हिन्दी हो सम्पर्क की भाषा,
इसका क्यों कर रहे विरोध।
कारण केवल वोट सियासत,
जन-मन चाहे कर ले शोध।।

सरकार ने केंद्र के विभाज्य पूल में से किसी राज्य की कर हिस्सेदारी नहीं घटाई है : वित्त मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को केंद्र से उनकी कर हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं होने संबंधी कुछ विपक्षी सांसदों के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार ने केंद्र के विभाज्य पूल में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया है। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सरकार ने बजट में पांच मेडिकल क्लस्टर, पांच मेगा औद्योगिक पार्क, बुजुर्ग देखभाल के लिए पेशेवरों को तैयार करने जैसी कई घोषणाएं की हैं जिनसे लाखों रोजगारों का सृजन होगा।

सीतारमण ने कहा, ''हम पर आरोप लगता है कि हम राज्यों की 41 प्रतिशत कर हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं करते। मैं सदन के माध्यम से आश्वासन देती हूं कि हमने केंद्र के विभाज्य पूल में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया है।'' वित्त मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने 2018-19 से 2022-23 तक राज्यों की कर हिस्सेदारी का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि केंद्र से राज्यों को मिलने वाला यह धन आयोग की सिफारिश से पूरी तरह मेल खाता है और इसमें कोई कमी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कुल कर हस्तांतरण 25.44 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 2.07 लाख करोड़ रुपये अधिक होगा।

सीतारमण ने कहा कि संविधान ने केंद्र को उपकर और अधिशेष लगाने का अधिकार दिया है और विभाज्य पूल में वह शामिल नहीं होता है, इसलिए राज्यों की कुल कर हिस्सेदारी की बात करते समय उपकर और अधिशेष संबंधी आरोप अनुचित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र जो उपकर वसूलता है उसमें से भी राज्यों को अस्पताल, स्कूल और सड़क आदि के निर्माण के लिए सहायता देता है।

सीतारमण ने कहा कि यह बजट इस सदी के दूसरे चतुर्थांश के पहले साल का बजट है और इसमें 2026 से लेकर 2050 तक के कई सारे विषयों को समाहित किया गया है और दीर्घकालिक निवेश की कई योजनाओं की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) पर विशेष ध्यान देते हुए बजट में स्पष्ट घोषणा की है कि जिन मध्यम उद्योगों की निर्यात बढ़ाने की क्षमता है, उन्हें और मदद दी जाएगी।

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएंगे : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया और बिना आधार के गंभीर आरोप लगाए।

रिजिजू ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए स्पष्ट नियम हैं। यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे पहले नोटिस देना होता है और अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण भी पेश करने होते हैं। बिना नोटिस और बिना प्रमाण के आरोप लगाना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोई ठोस और उपयोगी सुझाव नहीं दिया, बल्कि सिर्फ 'बेबुनियाद और जंगली आरोप' लगाए। रिजिजू ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से कहा था कि जब वित्त मंत्री शाम 5 बजे बजट पर जवाब देंगी, तब वे सदन में मौजूद रहकर अपनी बातों को साबित करें। रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में सरकार छोड़ने से पहले दिए गए उनके भाषण और पीआईबी की आधिकारिक रिलीज में साफ लिखा था कि 2030 के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।

सरकार वाहन उद्योग की वृद्धि के लिए स्थिर नीतिगत माहौल देने को प्रतिबद्ध : कुमारस्वामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भारत ने प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ संतुलित और रणनीतिक जुड़ाव अपनाया है। यूरोपीय संघ के साथ समझौता गैर-शुल्क बाधाओं, नियामकीय सहयोग और विशेषकर उत्सर्जन टिकाऊपन और उन्नत वाहन प्रौद्योगिकियों में मानक समन्वय पर केंद्रित है।

नई दिल्ली/भाषा। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार का स्थिर नीतिगत माहौल बनाए रखने पर ध्यान है ताकि घरेलू वाहन कलपुर्जा उद्योग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकार देने में अहम भूमिका निभा सके। कुमारस्वामी ने वाहन कलपुर्जा विनिर्माताओं के संगठन एक्मा के एक कार्यक्रम में कहा कि विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहे भारत के लिए अगली पीढ़ी की आपूर्ति श्रृंखलाओं में वाहन कलपुर्जा उद्योग केंद्रीय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्की एवं हल्के वजन वाली सामग्री और बुद्धिमत्ता प्रणाली जैसे क्षेत्रों में नवाचार वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सरकार स्थिर नीतिगत माहौल देने, प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने और उद्योग के साथ मिलकर पैमाना, गुणवत्ता और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारतीय विनिर्माताओं को केवल वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदार बनाना ही नहीं, बल्कि उनमें नेतृत्व की भूमिका निभाने के लायक बनाना है।

कुमारस्वामी ने व्यापार के मोर्चे पर कहा, भारत ने प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ संतुलित और रणनीतिक जुड़ाव अपनाया है। यूरोपीय संघ के साथ समझौता गैर-शुल्क बाधाओं, नियामकीय सहयोग और विशेषकर उत्सर्जन टिकाऊपन और उन्नत वाहन प्रौद्योगिकियों में मानक समन्वय पर केंद्रित है। उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत चुनिंदा वाहन कलपुर्जों को तरजीही बाजार पहुंच देने संबंधी प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय वाहन उद्योग को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक बताते हुए कहा कि वाहन उत्पादन 2023-24 के 2.84 करोड़ इकाइयों से बढ़कर 2024-25 में करीब 3.1 करोड़ इकाइयों तक पहुंच गया है। इस दौरान वाहन निर्यात भी 45 लाख से बढ़कर 53 लाख इकाई से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार दुर्लभ मृदा विनिर्माण और संबंधित गलियारों के निर्माण सहित विभिन्न पहल के जरिये इस क्षेत्र को समर्थन दे रही है। केंद्रीय बजट में निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, जिससे भारी इंजीनियरिंग और अवसंरचना विकास को बल मिलेगा।

भारतीय वायु सेना नई पीढ़ी के और अधिक विमान शामिल करने की इच्छुक : उपप्रमुख

नई दिल्ली/भाषा। वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने बुधवार को कहा कि भारतीय वायु सेना अपने बेड़े में नई पीढ़ी के और भी अधिक विमानों को शामिल करने की इच्छुक है।

कपूर वायु शक्ति अभ्यास से पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। राफेल के बारे में उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल निश्चित रूप से अन्य नायकों के साथ-साथ एक नायक था। जी हां, राफेल इन दिनों एक चर्चित शब्द बन चुका है; यह निश्चित रूप से चर्चा के केंद्र में है।

वायुसेना के उपप्रमुख ने कहा, वायुसेना और भी कई एमआरएफए (बहु-भूमिका लड़ाकू विमान) को शामिल करने का इच्छुक है, चाहे वह राफेल हो या कोई अन्य विमान, इस पर फिलहाल विचार चल रहा है। और इस संबंध में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

कपूर ने कहा, भारतीय वायु सेना अपने बेड़े में नई पीढ़ी के और अधिक विमान शामिल करने के लिए उत्सुक है, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है।

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने इसी कार्यक्रम में बताया कि आगामी वायु शक्ति अभ्यास में राफेल, एसयू-30, मिग-29, तेजस, जगुआर और अन्य लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय वायु सेना के सफल योगदान को प्रदर्शित करेंगे।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में सरकार ने 'भारत माता' को बेच दिया : राहुल गांधी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है। उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि भारत-अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट के समांतर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ है।

राहुल गांधी ने कहा, ''अमेरिका और चीन के बीच मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत का डेटा है। अगर अमेरिका महाशक्ति बने रहना चाहता है और डॉलर की रक्षा करना चाहता है तो अमेरिकियों के लिए भारत का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या त्रासदी है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह ताकत है।'' राहुल गांधी ने कहा कि ''अगर 'विपक्षी इंडिया' गठबंधन की सरकार होती और व्यापार समझौते की बात करती तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कहते कि आप के डॉलर की सुरक्षा करने की सबसे बड़ी पूंजी (डेटा) भारतीय लोगों के पास है।''

उन्होंने कहा, ''हम बराबरी पर बात करते। हम कहते कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि हम आपके नौकर हैं। हम अमेरिकी राष्ट्रपति से यह भी कहते कि हम अपने ईंधन की रक्षा करने जा रहे हैं। हम यह भी कहते हैं कि आप अपने किसानों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम भी अपने किसानों की रक्षा करेंगे।''

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के बराबर नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में शुल्क पहले तीन प्रतिशत के आसपास था, जो अब 18 प्रतिशत हो गया है यानी छह गुना बढ़ोतरी हो गई है।

राहुल गांधी ने कहा, वहीं, अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क 16 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया। उन्होंने दावा किया, अब यह होगा कि अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीदेंगे और भारत के प्रधानमंत्री मोदी फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया, हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं...आपने हमारे किसानों को कुचले जाने का रास्ता खोला है। आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और आगे भी कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते में भारत को बेच दिया गया, मां (मदर) को बेच दिया गया, भारत माता को बेच दिया गया, जिस पर सरकार को शर्म आनी चाहिए।

सावा

राजस्थान के बीकानेर में मंगलवार को पुष्करणा ओलंपिक विवाह समारोह के दौरान घोड़ी पर सवार होकर एक दुल्हन अपने ससुराल पहुंची।

'जन गण मन' से पहले गाया जाएगा 'वंदे मातरम'

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में 'वंदे मातरम' बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई। पीटीआई भाषा के अनुसार आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' साथ में गाए या बजाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी।

समान नागरिक संहिता भारत की समावेशी सोच को मजबूत करेगी : मुख्तार नकवी

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि समान नागरिक संहिता भारत की मूलभूत संवैधानिक भावना और समावेशी सोच को मजबूत करेगी। नकवी ने कहा कि जो लोग इस संवैधानिक सुधार को ''सांप्रदायिक रूप से निशाना बनाने'' में शामिल हैं, वे न तो देश के और न ही किसी धर्म के शुभचिंतक हैं। उन्होंने दावा किया कि इस संवैधानिक सुधार का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना है। उन्होंने यहां गार्गी कॉलेज में कहा, ''संविधान की शक्ति को दुर्भावनापूर्ण साजिशों से बचाना भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य है।''

नकवी लोकसभा सचिवालय के संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा आयोजित संवैधानिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों पर एक युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री ने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता बहुसंख्यक समुदाय की समावेशिता, सह-अस्तित्व और सहिष्णुता के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा, ''विभाजन की भयावहता के बाद जहां भारत के हिंदू बहुसंख्यक समुदाय ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग चुना, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय ने इस्लामी राष्ट्र का झंडा फहराया। भारतीय संविधान की विविधता में एकता की समावेशी और व्यापक सोच बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों, संकल्प और संस्कृति का परिणाम है।'' नकवी ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की शक्ति ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में सत्ता का निर्धारण ''बैलट'' (मतदान) के माध्यम से होता है, न कि ''बुलेट''(गोली) के माध्यम से।

जांच

देहरादून में तिब्बती मार्केट के पास बदमाशों द्वारा एक युवक की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस मौके पर सबूत इकट्ठा करते हुए।

तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा : स्टालिन

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और कांग्रेस के बीच दरार की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए बुधवार को कहा कि गठबंधन पूरी तरह से कायम है। उन्होंने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा उठाए जा रहे संभावित गठबंधन सरकार के सवाल को भी खारिज कर दिया।

द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने स्पष्ट किया कि कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार में सत्ता साझा करना तमिलनाडु को नहीं भाता है। कांग्रेस इस बात को भली-भांति जानती है। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, कुछ लोग केवल गठबंधन में फूट डालने के लिए सत्ता-साझा करने का मुद्दा उठा रहे हैं। यह चाल काम नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में भ्रम की अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति अपने व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा, मैं उन्हें भाई मानता हूं और वह भी मुझे उसी नजर से देखते हैं।

कांग्रेस 2013 में डब्ल्यूटीओ की बैठक में समझौता करके आई थी : सीतारमण का राहुल पर पलटवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बैठक में किसानों के हितों से समझौता करके आई थी।

उन्होंने बजट पर चर्चा में राहुल के भाषण को लेकर उन पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करके नरेन्द्र मोदी सरकार ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है और उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है। सीतारमण ने बजट पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 2013 में (इंडोनेशिया के) बाली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जाकर कांग्रेस समझौता करके आई थी। उन्होंने दावा किया, इस समझौते के कारण 2017 से भारत में किसान से कोई खरीद नहीं हो सकती थी। हम राशन की दुकान से गरीबों को कुछ नहीं दे सकते थे।

सीतारमण ने कहा कि इस समझौते के कारण देश में 2017 से पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) की सामग्री का वितरण नहीं हो सकता था। उन्होंने आरोप लगाया, गरीब को, किसान को, बेचने वाले ये लोग थे। डब्ल्यूटीओ में 'सरेंडर' करके ये लोग आये। नेता प्रतिपक्ष को (नरेन्द्र मोदी) सरकार पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि

201% में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस समझौते के प्रावधान बदले थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भारत के हित में बोलेंगे।

सीतारमण ने कहा कि राहुल ने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल को अपना दोस्त बताया, जबकि उनकी पार्टी (कांग्रेस) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए रवनीत बिट्टू को 'गद्दार'' कहा। सीतारमण ने सवाल किया, ''आसन पर बैठे व्यक्ति यदि दोस्त हैं तो हमारे (भाजपा के) बिट्टू गद्दार कैसे हो गए।'' वित्त मंत्री ने कहा कि डेटा को लेकर राहुल के आरोप गलत हैं और नेता प्रतिपक्ष ने बजट के प्रावधान नहीं पढ़े हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत एक हजार करोड़ रुपये का बजट इस विषय के लिए आवंटित किया गया है जिससे डेटा सुरक्षित होगा। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन (नेता प्रतिपक्ष) बात करने के लिए। सरकार डेटा केंद्रों को प्रोत्साहन दे रही है ताकि डेटा भारत में ही रहे। उन्होंने राहुल के इस दावे की कड़ी आलोचना की कि भारतीय डेटा देश से बाहर चला जाएगा।

उन्होंने विपक्षी दल पर प्रहार करते कहा, ''कांग्रेस के लोगों को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए।'' मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कुछ सदस्यों की टोकाटोकी पर सीतारमण ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना (उबाठा) नीत तत्कालीन सरकार समय पर जमीन आवंटित कर देती तो भारत में बुलेट ट्रेन चल रही होती।

जिम्मेदारी का निर्वाह सावधानीपूर्वक न हो तो अदालती प्रक्रिया दंड का रूप ले सकती है : न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश व्यापमं परीक्षा घोटाले में एक व्हिसलब्लोअर के खिलाफ जाति-आधारित हिंसा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कानून के शासन के प्रति निष्ठा के लिए अदालत को यह याद रखना आवश्यक है कि यदि इस जिम्मेदारी का सावधानीपूर्वक निर्वाह नहीं किया जाता, तो प्रक्रिया स्वयं ही सजा बन सकती है।

आनंद राय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2022 में एक रैली के दौरान एक सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित हिंसा और दुर्व्यवहार से जुड़े जाति-आधारित अत्याचारों के मामले में आरोप तय करने को बरकरार रखा गया था। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राय के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अदालत को जानबूझकर एक वास्तविक मामले और एक ऐसे मामले के बीच अंतर करना चाहिए जो केवल संदेह या अनुमान पर आधारित हो।

शीर्ष अदालत ने कहा, 22प्रथम दृष्टया मामला न होने के बावजूद किसी मामले को आगे बढ़ने देना, किसी व्यक्ति को कानूनी आवश्यकता के बिना आपराधिक कार्यवाही के तनाव और अनिश्चितता के हवाले करना है। कानून के शासन के प्रति निष्ठा के लिए न्यायालय को यह याद रखना आवश्यक है कि यदि इस जिम्मेदारी का सावधानीपूर्वक निर्वाह नहीं किया गया तो प्रक्रिया स्वयं ही दंड बन सकती है।'' मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप साबित करने के लिए कई तत्वों का मौजूद होना आवश्यक है। पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आरोपी को यह जानकारी होनी चाहिए कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या संपत्ति ऐसे व्यक्ति की है।

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात की

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पदभार संभालने के एक दिन बाद बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी अलग से मुलाकात की। वह मंगलवार रात को दिल्ली पहुंची थीं। महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वालीं सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उनके बेटे पार्थ और जय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे भी साथ थे। पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में अपने पति और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु के कुछ दिनों बाद, सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में उनका स्थान लिया।

वृन्दावन में उद्घाटन के दिन ही नवनिर्मित होटल में आग लगी, महिला सहित तीन झुलसे

मथुरा (उप्र)/भाषा। मथुरा जिले के वृन्दावन स्थित नवनिर्मित एक होटल में बुधवार को उद्घाटन के दिन ही आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक महिला व दो बच्चे झुलस गये। ये तीनों होटल मालिक के परिवार के सदस्य हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि राया नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल ने रुक्मिणी विहार में एक नया होटल बनाया है। उन्होंने बताया कि आज ही होटल का उद्घाटन किया गया था, और कुछ घंटे बाद ही जब होटल मालिक के परिजन वहां घूम रहे थे, तभी अचानक आग लग गई। सिंह ने कहा कि आग संभवत: शार्ट सर्किट के कारण लगी हो, लेकिन इस बात की पूरी जांच कराई जाएगी कि होटल को चालू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमति ली गई हों। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अग्निशमन दल ने आग पर कुछ समय में ही काबू पा लिया।

लैंबॉर्गिनी टक्कर मामले में आया नया मोड़ : 'मुआवजा' मिलने के बाद वादी ने वापस ली शिकायत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कानपुर/भाषा। उत्तर प्रदेश में कानपुर के हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी टक्कर मामले की जांच में बुधवार को उस समय एक नया मोड़ आ गया, जब मामले में मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने 'मुआवजा' मिलने के बाद इस सिलसिले में आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करने की इच्छा जाहिर की। एक अन्य घटनाक्रम में कार के कथित चालक मोहनलाल ने आज ही दावा किया कि जब कार ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मारी, तो तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा नहीं बल्कि वह खुद गाड़ी चला रहा था। शिवम के वकील धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना के मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले ई-रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक (18) ने कहा है कि उसका आरोपी पक्ष से समझौता हो गया है और अब वह इस मामले में चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। सिंह ने दावा किया कि दुर्घटना के समय मोहनलाल कार चला रहा था और उसने तौफीक के इलाज के खर्च और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि तौफीक के पैर और हाथ में चोटें आई थीं। तौफीक को पहले उर्सुला हॉर्समैन मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया था और बाद में आगे की मेडिकल जांच तथा एक्स-रे के लिए स्वरूप नगर के एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया। इसके बाद तौफीक को ग्वालटोली थाने में बुलाया गया, जहां ग्वालटोली के तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार गौड़ की मौजूदगी में उसके और कथित कार चालक मोहनलाल के बीच एक लिखित समझौते पर दस्तखत हुए। इस दौरान तौफीक को कथित रूप से मुआवजे

के तौर पर 20 हजार रुपये दिये गये। समझौता दस्तावेज में कहा गया है कि यह समझौता बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से किया गया है और शिकायतकर्ता लैंबॉर्गिनी टक्कर मामले में उसके चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। हालांकि, एक और वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस हाई-प्रोफाइल मामले के तुरंत बाद मामले को जल्दी खत्म करने के लिए 'उच्च अधिकारियों के काफी दबाव' में यह समझौता हुआ है।

इससे पहले, कथित कार चालक मोहनलाल ने यहां एक अदालत के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हादसे से कुछ देर पहले शिवम को अचानक दौरा पड़ा था और उसे संभालने की कोशिश में वह कार पर नियंत्रण खो बैठा था। उसने कहा, जब यह हादसा हुआ तब मैं कार चला रहा था। अचानक शिवम को दौरा पड़ा और वह मेरे ऊपर गिर गया। मैं डर गया और मैंने उसे एक हाथ से संभालने की कोशिश की। कार एक तिपहिया वाहन से टकराई, डिवाइडर पर चढ़ी और रुक गई। मोहनलाल ने आगे दावा किया कि गाड़ी के ऑटोमैटिक लॉकिंग सिस्टम की वजह से वह तुरंत कार से बाहर नहीं निकल पाया। मोहन ने कहा, मैंने उसे चालक की सीट पर बैठाया और बाहर निकल गया। बाद में शीशा टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि कार चालक के वकील ने संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण की अर्जी दी थी और अर्जी के बाद मोहनलाल बुधवार को आत्मसमर्पण करने के लिए अदालत में पेश हुआ। हालांकि, ग्वालटोली पुलिस ने अदालत में जमा अपनी रिपोर्ट में उसे मामले में आरोपी नहीं बनाया।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के रुख को देखते हुए अदालत ने उसका आत्मसमर्पण स्वीकार करने से मना कर दिया। लैंबॉर्गिनी एक इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। गत रविवार की अपराह्न करीब तीन बजे ग्वालटोली इलाके में लैंबॉर्गिनी कार वीआईपी रोड पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों से टकरा गई। इस मामले में घायलों में से एक तौफीक ने बाद में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और अन्य सुबूत बताते हैं कि हादसे के समय शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन वीडियो का भी उल्लेख किया जिनमें टक्कर के तुरंत बाद कुछ लोग चालक की सीट से एक आदमी को खींचते हुए दिख रहे हैं जो शिवम लग रहा है। पुलिस उपायुक्त (मध्य) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जांच में शिवम की भूमिका 'साफ तौर पर साबित' हो गयी है।

आरएसएस कार्यक्रम में सलमान खान को आमंत्रित करने में गलत क्या है? : शिंदे

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संघ प्रमुख मोहन भगवत द्वारा संबोधित एक कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान को आमंत्रित किए जाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का बचाव करते हुए सवाल किया कि आखिर समारोह में फिल्म अभिनेता की उपस्थिति में गलत क्या था। खान समेत कई फिल्मी हस्तियां सप्ताहांत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं जिसे भागवत ने संबोधित किया था। मुंबई के नेहरू केंद्र में आयोजित यह कार्यक्रम आरएसएस के शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया था।

शिंदे ने कहा कि खान भारतीय नागरिक हैं तथा देश की परंपराओं और संस्कृति में विश्वास रखते हैं। सत्तारूढ़ शिवसेना के प्रमुख शिंदे ने मंगलवार को पूछा, आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान को आमंत्रित करने में गलत क्या है? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और देशभक्ति आरएसएस कार्यकर्ताओं के रोम रोम में बसी है। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान को भागवत के साथ बातचीत करते देखे जाने के बाद शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में आरएसएस पर कटाक्ष किया था।

भाजपा पार्षद रितु तावडे मुंबई की महापौर चुनी गईं, शिवसेना के संजय घाडी उपमहापौर बने

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पार्षद रितु तावडे बुधवार को मुंबई की महापौर चुनी गईं, जबकि शिवसेना के संजय घाडी उप महापौर बने। दोनों को इन पदों के लिए निर्विरोध चुना गया।

तावडे के महापौर बनने के साथ ही भाजपा ने 44 वर्षों के बाद देश के सबसे अमीर नगर निकाय में महापौर के पद पर कब्जा जमा लिया। वह मुंबई में भाजपा की दूसरी महापौर हैं। मुंबई में पहली बार भाजपा का महापौर 1982-83 में बना था, जब प्रभाकर पाई इस पद पर थे। बुधवार को तावडे के चुने जाने से मुंबई की राजनीति में ठाकरे परिवार का दबदबा समाप्त हो गया। बीएमसी की विशेष आम सभा में तावडे और घाडी दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। शिवसेना (उबाठा) और अन्य विपक्षी दलों ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। बीएमसी मुख्यालय में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सत्ताधारी और विपक्षी दलों के पार्षदों की नारेबाजी के बीच तावडे ने मुंबई की 78वीं महापौर के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विस अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और भाजपा व शिवसेना के अन्य नेता समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने नव निर्वाचित महापौर और उपमहापौर को बधाई दी। नगर निकाय के लिए 15 जनवरी को हुए चुनाव में तावडे वार्ड 132, जबकि घाडी वार्ड-पांच से निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित सदन के अभाव में, बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी मार्च 2022 से नगर निकाय के कामकाजों की देखरेख कर रहे थे। इससे पहले, गगराणी ने राज्य द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी के रूप में बीएमसी के कमिटी हॉल में चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया।

इंस्टाग्राम पर ईसी झाड़ने वाला प्रेमी 'दिहाड़ी मजदूर' निकला, पति के पास लौटी महिला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुमका/भाषा। झारखंड के दुमका में पति और तीन बच्चों को छोड़कर एक महिला ने आंध्र प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दिया, जिससे वह सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर मिली थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक महिला को वापस झारखंड लाया गया है। महिला के पति द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम पहुंचने पर, महिला को पता चला कि इंस्टाग्राम पर मिला वह व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर था, न कि अमीर, जैसा कि उसने सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान दावा किया था। सरैयाहाट पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी राजेंद्र कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि माता-पिता के समझाने पर 30 वर्षीय महिला वापस लौटने के लिए राजी हो गई और उसके पति ने भी उसे स्वीकार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, महिला के पति ने 12 जनवरी को अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया था कि उनकी पत्नी लंबे समय से इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति से बात करती थी और इस मुद्दे पर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस होती थी। इस सूचना के आधार पर, स्थानीय पुलिस ने तकनीकी निगरानी पर आधारित एक टीम को आंध्र प्रदेश भेजा और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में महिला का पता लगाया।

'धनवर्षा' का झांसा देकर 'जहरीले लड्डू' खिलाकर तीन लोगों की हत्या के आरोप में तांत्रिक को किया गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों की हत्या के आरोप में बुधवार को एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। तांत्रिक पर आरोप है कि उसने 'धनवर्षा' का वादा करते हुए एक अनुष्ठान करने के नाम पर उन्हें जहर मिले ''लड्डू'' खिलाकर मार डाला। आरोपी की पहचान कमरुद्दीन उर्फ बाबा के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का निवासी है। वह लोनी और फिरोजाबाद में एक तथाकथित तांत्रिक केंद्र संचालित कर रहा था और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में दर्ज दो अलग-अलग हत्या के मामलों में वांछित था।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी) सचिन शर्मा ने बताया, ''विस्तृत तकनीकी और जमीनी स्तर पर जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वह लोगों की हत्या करने और उनसे नकदी और कीमती सामान लूटने की सुनियोजित साजिश में शामिल था।'' अधिकारी ने बताया कि कमरुद्दीन तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से भारी धन लाभ का वादा करके लोगों को शिकार बनाता था। उनका विश्वास जीतने के बाद वह कथित तौर पर उन्हें जहर मिले लड्डू खिलाता था तथा शराब और शीतल पेय पिलाता था, जिसके बाद जब वे बेहोश हो जाते थे तो वह उनका पैसा लेकर फरार हो जाता था।

उन्होंने बताया, ''यह मामला आठ फरवरी को तब सामने आया जब पश्चिम विहार पूर्व पुलिस थाने को एक पीसीआर से जानकारी प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक महिला सहित तीन लोग एक कार के अंदर बेहोश पड़े हैं।'' पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें चालक की सीट पर करीब 76 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति और कार के अंदर करीब 40 वर्षीय महिला मिली। साथ ही 42 वर्षीय एक व्यक्ति को राहगीरों ने बाहर

निकाल लिया गया था।

शर्मा ने बताया, ''तीनों को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को शराब की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, खाली गिलास, मोबाइल फोन, नकदी, हेलमेट, जैकेट, आधार कार्ड और अन्य व्यक्तिगत सामान और दस्तावेज मिले।'' उन्होंने बताया कि तीनों की पहचान बापरोला निवासी रणधीर (76), नगली डेयरी के प्रॉपर्टी डीलर शिव नरेश (42) और जहांगीरपुरी निवासी लक्ष्मी (40) के रूप में हुई है। मृतक के परिवार वालों ने आत्महत्या की आशंका से इनकार किया था और उनकी मौत की परिस्थितियों पर संदेह व्यक्त किया था, जिसके कारण पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने कहा कि तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चला है कि घटना से पहले के दिनों में तीनों कमरुद्दीन के संपर्क में थे और गाजियाबाद के लोनी गए थे - पहली बार घटना से एक दिन पहले और फिर उसी दिन जब वे मृत पाए गए थे। पुलिस को पता चला कि जब तीनों दिल्ली लौट रहे थे तब कार में एक और व्यक्ति मौजूद था।

अधिकारी ने बताया, आगे की जांच से पता चला कि वह व्यक्ति कमरुद्दीन था, जो लोनी में वाहन में सवार हुआ था और बाद में उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया था जहां वह मिला था। डीसीपी ने कहा कि कमरुद्दीन को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसने जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी गतिविधियों के बारे में संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा। लगातार पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि लगभग दो महीने पहले जहांगीरपुरी निवासी सलीम नामक व्यक्ति के माध्यम से लक्ष्मी से उसकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद लक्ष्मी ने शिव नरेश और रणधीर का परिचय उससे कराया। पुलिस ने बताया कि कमरुद्दीन ने तीनों को 'धनवर्षा' के लिए ''एक विशेष पूजा'' करने के लिए राजी किया और उन्हें अनुष्ठान के लिए दो लाख रुपये नकद के साथ-साथ शराब और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

घटना वाले दिन उसने कथित तौर पर जहर मिलाकर लड्डू तैयार किए और तीनों को लोनी से दिल्ली तक कार में ले गया। यात्रा के दौरान उसने ''अनुष्ठान'' के हिस्से के रूप में उन्हें शराब, कोल्ड ड्रिंक और जहरीली मिठाइयां दीं। अधिकारी ने बताया, ''उसके खुलासे के अनुसार तीनों जहर वाले लड्डू और पेय पदार्थ का सेवन करने के बाद अस्वस्थ महसूस करने लगे और अंततः बेहोश हो गए। इसके बाद वह नकदी लेकर फरार हो गया।''

पुलिस ने कहा कि साक्ष्यों से घटना के समय पर कार में कमरुद्दीन की उपस्थिति की पुष्टि होती है। मार्ग के सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और लोकेशन डेटा ने भी घटनाक्रम की पुष्टि की है। अधिकारी ने बताया कि कमरुद्दीन आदतन अपराधी है और इससे पहले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसी तरह के हत्या के दो मामलों में शामिल रहा है।

उन्होंने बताया, ''उस पर इससे पहले 2014 में राजस्थान के धौलपुर स्थित राजा खेड़ा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 363 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा, 2025 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित मक्खनपुर पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 103(1) और 123 के तहत एक अन्य प्राथमिकी में भी उसका नाम दर्ज किया गया था।''

पुलिस ने पश्चिम विहार पूर्व पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया है। अपराध में किसी और की संलिप्तता का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और कांग्रेस के बीच दरार की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए बुधवार को कहा कि गठबंधन पूरी तरह से कायम है। उन्होंने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा उठाए जा रहे संभावित गठबंधन सरकार के सवाल को भी खारिज कर दिया।

द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने स्पष्ट किया कि कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार में सत्ता साझा करना तमिलनाडु को नहीं भाता है। कांग्रेस इस बात को भली-भांति जानती है। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, कुछ लोग केवल गठबंधन में फूट डालने के लिए सत्ता-साझा करने का मुद्दा उठा रहे हैं। यह चाल काम नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में भ्रम की अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति अपने व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा, मैं उन्हें भाई मानता हूं और वह भी मुझे उसी नजर से देखते हैं।

स्टालिन ने दोहराया कि द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन सामंजस्यपूर्ण है और जो लोग इसके टूटने की उम्मीद कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी इस मायने में अहम है कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे की वार्ता में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की है। मंगलवार को कांग्रेस के तमिलनाडु और पुडुचेरी मामलों के प्रभारी गिरीश चोडणकर ने आगामी (तमिलनाडु) विधानसभा चुनाव से पहले वार्ता के लिए सीट-बंटवारा समिति के गठन में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) द्वारा की जा रही देरी' पर चिंता व्यक्त की।

द्रमुक ने घोषणा की कि 22 फरवरी से बातचीत शुरू करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी। कांग्रेस सांसदों मणिक्कम टैगोर, ज्योतिमणि और मदुरै के द्रमुक नेता जी थलपति के बीच सत्ता-साझाकरण को लेकर हुई जुबानी जंग के बाद द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन को लेकर व्यापक अटकलें लगाई जा रही थीं।

द्रमुक मंत्री आर एस राजकन्नप्पन ने 10 फरवरी को कहा था, कांग्रेस में एक-दो लोग गड़बड़ी पैदा करते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं, तो वे नाराज हो जाते हैं। वे गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर वे रहना चाहते हैं, तो रहें। गठबंधन में रहना या न रहना थलाइवर (स्टालिन) पर निर्भर करता है।

उन्होंने पूछा, जब कलाइग्नार (द्रमुक संरक्षक एम. करुणानिधि) ने 100-111 सीट जीतीं, तब भी क्या उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी दी? उन्होंने पुदुकोट्टाई में कहा, जब द्रमुक 150 सीट जीतने की दहलीज पर है, तो हम कैसे हिस्सा दे सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से, केवल थलपति (एम.के. स्टालिन) ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। आपको जो चाहिए, हम वह करेंगे। केवल द्रविड़ मॉडल की सरकार ही बनेगी।

विपक्षी दल ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके) के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन की स्थिरता पर संदेह जताते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन टूटने की कगार पर है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन से अलग हो जायेगी। आज कार्यक्रम में स्टालिन ने कहा कि आगामी तमिलनाडु चुनाव द्रमुक के लिए 2021 विधानसभा चुनाव से अधिक कठिन नहीं होंगे।

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा का फासीवाद कभी नहीं जीतेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को पेश किए गए बजट पर उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार ने बजट में तमिलनाडु को शून्य दिया है। भाजपा को चुनाव में भी शून्य सीट मिलेगी।'' उन्होंने राज्य सरकार की कुछ योजनाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि केंद्र सरकार भी कुछ योजनाओं को अपना रही है, जैसे 'थोझी' छात्रावास योजना। यह योजना उन महिलाओं की चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाई गई है, जो अपने गृह नगर से शहरों में काम करने आती हैं। सामाजिक कल्याण और महिला विकास विभाग द्वारा संचालित इन छात्रावासों में राज्यभर की कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित, किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जाता है।

अशोक लेलैंड का तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 5.19% बढ़कर 862.24 करोड़ रुपये

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 5.19 प्रतिशत बढ़कर 862.24 करोड़ रुपये हो गया। वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी ने बुधवार को अपने तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की जानकारी दी।

अशोक लेलैंड ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 819.67 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय बढ़कर 14,830.24 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,995.21 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 13,490.15 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 10,937.89 करोड़ रुपये था। प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए अशोक लेलैंड के कार्यकारी चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा, ''कंपनी की बिक्री मात्रा और मुनाफे में लगातार और मजबूत वृद्धि यह दर्शाती है कि हमारा उत्पाद पोर्टफोलियो प्रतिस्पर्धी है।''

गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सत्ता साझा नहीं करना सामाजिक न्याय के विरूद्ध : टीवीके

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। टीवीके नेता के जी अरुणराज ने बुधवार को कहा कि द्रमुक अपने सहयोगियों को सत्ता में हिस्सेदारी दिए बिना उनका इस्तेमाल केवल वोट हासिल करने के लिए कर रही है और ऐसा करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब सत्ताधारी द्रमुक और उसके प्रमुख सहयोगी कांग्रेस के बीच सत्ता-साझा करने को लेकर खींचतान चल रही है।

जहां लोकसभा सदस्य मणिक्कम टैगोर समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्ता-साझा करने को लेकर मुखर हो रहे हैं वहीं द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन तो बरकरार है, लेकिन राज्य में सत्ता साझा करने की कोई संभावना नहीं है।

अरुणराज ने कहा, ''अगर आप स्थिति पर गौर करें तो एक बात पर बारीकी से ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री (एम.के. स्टालिन) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुर्सी को देखें तो उसका सिर्फ एक पैर द्रमुक का है, बाकी गठबंधन दलों के हैं। ऐसे में गठबंधन दलों को सत्ता में हिस्सेदारी दिए बिना सिर्फ वोट हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है।''

पूर्व आईआरएस अधिकारी ने पूछा, ''भले ही उसने (द्रमुक ने) 130 से अधिक सीटें जीत ली हों, लेकिन गठबंधन दलों का योगदान हर एक निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद है। क्या वह इसे नकार सकती है?''

एलंगोवन ने कांग्रेस के द्रमुक पर दबाव बनाए जाने की खबरों को खारिज किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता टी.के.एस. एलंगोवन ने बुधवार को उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी पर अनावश्यक दबाव बना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत 22 फरवरी से शुरू होगी।

एलंगोवन का यह बयान द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन में दरार की बढ़ती अटकलों के बीच आया है। खबरों के मुताबिक, कांग्रेस इस बार सत्ता में हिस्सेदारी और कम से कम 40 सीटों की मांग कर रही है जबकि

2021 के चुनाव में उसने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, द्रमुक कथित तौर पर अपनी 2021 की स्थिति को ही बरकरार रखना चाहती है।

एलंगोवन ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, मुझे नहीं पता कि यह क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस दबाव डाल रही है। न तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष (मल्लिकार्जुन खरगे) और न ही कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई (टीएनसीसी) के अध्यक्ष (के. सेल्वापेरुन्थागई) ने हम पर कोई दबाव डाला है।

पूर्व सांसद ने कहा कि इस तरह के दावे संभवतः कांग्रेस के कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा फैलाए जा रहे हैं जो केवल दिखावा करना चाहते हैं। गठबंधन की रणनीति पर स्पष्टता देते हुए एलंगोवन ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा शुरू करने के लिए 22 फरवरी का समय तय किया है। यह घटनाक्रम टीएनसीसी के उस हालिया सार्वजनिक आग्रह के बाद आया है, जिसमें द्रमुक से तुरंत वार्ता समिति बनाने की अपील की गई थी ताकि अंतिम समय की देरी से बचा जा सके। इसके लिए कांग्रेस पहले ही अपनी पांच सदस्यीय समिति गठित कर चुकी है।

जनता तय करेगी कि तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार होगी या एक दल की : कांग्रेस सांसद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ही तय करेगी कि राज्य में गठबंधन सरकार बनेगी या किसी एक दल की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। उन्होंने यह दावा भी किया कि कांग्रेस ने 2006 में जनादेश पर अमल न करने की 'गलती' की।

विरुधुनगर के सांसद टैगोर ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, जनता ही तय करेगी कि गठबंधन सरकार होगी या एकदलीय शासन। वर्ष 2006 में जनता के फैसले को लागू न करना हमारी गलती थी। कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव में द्रमुक के साथ गठबंधन में 25 सीट पर चुनाव लड़ा था तथा उसे 18 सीट मिली थीं।

तमिलनाडु में 2006 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने द्रमुक के साथ गठबंधन में 48 सीट पर चुनाव लड़ा था और वह 34 सीट जीती थी। तब द्रमुक ने 96 सीट जीतकर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाई। टैगोर ने 2006 के फैसले का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी पार्टी ने उस समय सरकार गठन में भाग नहीं लिया था।

द्रमुक सदस्य ने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में द्रमुक के सदस्य पी. विल्सन ने बुधवार को सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा उसके जांच और प्रवर्तन अधिकारों को मजबूत करने की मांग की, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए विल्सन ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ लक्षित हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। उन्होंने भीड़ द्वारा पीट पीट कर जान लेने की घटनाओं, पादरियों और धर्मगुरुओं पर हमले तथा चर्च और मस्जिदों में तोड़फोड़ की घटनाओं का उल्लेख करते हुए अपने तर्क के समर्थन में आंकड़ों का हवाला दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग कर एक ही मामले में कई प्राथमिकी दर्ज की जा रही हैं, यहां तक कि नाबालिगों के खिलाफ भी। उनके अनुसार, लोगों को

महीनों तक जेल में रखा जाता है और बाद में बरी कर दिया जाता है। उनके मुताबिक, 2020 से अब तक धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत करीब 400 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 1,200 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

विल्सन ने कहा कि ऐसे कदम संविधान में निहित समानता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के वादे के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय अल्पसंख्यकों को संस्थागत संरक्षण की सबसे अधिक जरूरत है, उसी समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक खाली दफ्तर बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद रिक्त हैं। कुछ पद पिछले 10 महीनों से खाली हैं, जबकि कुछ तीन वर्षों से अधिक समय से रिक्त पड़े हैं।

द्रमुक सदस्य ने कहा कि 2017-18 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आयोग को भेदभाव और हिंसा के मामलों में अप्रभावी बताया था और उसे तत्काल संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। वर्तमान में आयोग के पास केवल परामर्शात्मक अधिकार हैं। उन्होंने एक पूर्व अध्यक्ष के हवाले से कहा कि आयोग को दंतहीन बाघ कहा गया था क्योंकि उसके पास केवल सिफारिश करने की शक्ति है।

विल्सन ने सरकार से आयोग में रिक्त पदों को तत्काल भरने की अपील की। साथ ही उन्होंने भारत के संविधान और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में संशोधन कर आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को अपराध के रूप में परिभाषित किया जाए और आयोग को मामलों के पंजीकरण के निर्देश देने तथा जांच और प्रवर्तन संबंधी सशक्त अधिकार प्रदान किए जाएं।

केंद्र ने धान खरीद में नमी मानक में ढील संबंधी तमिलनाडु के आग्रह को खारिज किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के धान के लिए नमी मानक में ढील देने के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा है कि अधिक नमी वाले धान की खरीद से भंडारण में बड़ा जोखिम पैदा होता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस दक्षिणी राज्य ने धान के लिए नमी की सीमा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा कि अत्यधिक नमी वाले धान की खरीद से संचालन से जुड़े बड़े जोखिम पैदा होते हैं। मंत्री ने कहा कि अधिक नमी वाला धान तेजी से खराब होने, फफूंदी लगने, रंग बदलने और कीट संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और इन्हीं कारणों से नमी मानक में ढील देने पर विचार नहीं किया गया है।

तमिलनाडु राज्य भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि यह समिति भाजपा की चुनावी रणनीति की निगरानी करने के साथ-साथ पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगी। नागेंद्रन समिति के प्रमुख होंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पी. राधाकृष्णन को समन्वयक बनाया गया है। पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वरिष्ठ नेता एस आर शेखर, आर एन जयप्रकाश, एम वेंकटेशन, माला सेल्वकुमार और एस आर रामप्रियन सह-समन्वयक होंगे।

'विकसित केरलम' प्रशिक्षण के लिए दिल्ली आए केरल के भाजपा पार्षद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केरल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय प्रशासनिक और शासन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचा। इनके साथ केरल के अन्य नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं।

इस प्रतिनिधिमंडल में नगरपालिका अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और विधायी दल के नेता शामिल हैं, जो यहां राष्ट्रीय राजधानी में स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय में आयोजित होने वाले चार विशेष प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेंगे। भाजपा ने बुधवार को एक बयान में कहा, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें राज्य के अन्य नगर निकाय प्रतिनिधि भी शामिल हैं, महापौर वी.वी. राजेश के नेतृत्व में आज दिल्ली पहुंचा।

केरल के भाजपा नेताओं का यह दौरा 'भाजपा 4 विकसित केरलम' नामक एक व्यापक तीन दिवसीय प्रशासनिक और शासन कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे स्थानीय नेताओं को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक तंत्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बयान के मुताबिक, ''निर्वाचित प्रतिनिधि कल (बृहस्पतिवार) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे।''

नेतृत्व मुद्दे पर मुझे और शिवकुमार को पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करना चाहिए : सिद्दरामय्या

बेंगलूरु। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर मीडिया द्वारा बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बुधवार को कहा कि उन्हें और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान के निर्णय का पालन करना चाहिए।

सिद्दरामय्या ने मुख्यमंत्री पद के लिए उनके और शिवकुमार के बीच खींचतान के बीच कांग्रेस विधायकों की विदेश यात्रा की योजना बनाने की खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वे शायद अपने निजी खर्च पर जा रहे हैं। नाराज दिख रहे सिद्दरामय्या ने यहां पत्रकारों से कहा, ''क्या आप (मीडिया) इस (नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे) के अलावा कुछ और नहीं पूछ सकते? आप इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, सिर्फ यही। इसे शुरू किए हुए तीन महीने हो गए हैं। कृपया मुझसे यह सवाल दोबारा न पूछें।'' मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेस सांसद और शिवकुमार के भाई डीके सुरेश के उस बयान पर पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अनौपचारिक सत्ता-साझाकरण समझौते के संदर्भ में कहा था कि ''उन्हें अब भी उम्मीद है कि देरी होने के बावजूद मुख्यमंत्री अपना वादा निभाएंगे।''सिद्दरामय्या ने कहा, ''आलाकमान को सब पता है, वे फैसला करेंगे। मैं उनके फैसले का पालन करूंगा। मुझे आपको (पत्रकारों को) यह कितनी बार बताना पड़ेगा?'' उन्होंने कहा, ''चाहे मैं हो या शिवकुमार, हमें आलाकमान के फैसले का पालन करना चाहिए। यह मामला आलाकमान के निर्णय पर निर्भर है। आप (मीडिया) बार-बार यही सवाल पूछते हैं। क्या आपके पास पूछने के लिए और कुछ नहीं है?'' जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि वे सुरेश द्वारा दिए गए बयान पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, तो सिद्दरामय्या ने कहा, ''बयान देने वालों से पूछिए।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट किया पेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट (आय-व्ययक अनुमान) राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2026-27 में 21 लाख 52,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सदन की बैठक शुरू होते ही वित्त मंत्री ने राज्य के वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान विधानसभा में पेश किए। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।

उन्होंने कहा, विकसित राजस्थान2047 को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीत हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण एवं सुशासन को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने कहा, मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा किए गए ढांचागत सुधार व कुशल वित्तीय प्रबंधन से पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 21 लाख 52,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी 1.67 लाख रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर दो लाख के पार पहुंच जाएगी। अपने बजट भाषण में उन्होंने जलदाय विभाग में नई जल नीति लाने सहित अनेक घोषणाएं कीं।

नल से पानी उपलब्ध कराने के लिए 6,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2026-27 के राज्य बजट में ग्रामीण एवं शहरी आबादी को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 6,800 करोड़ रुपये का बुधवार को प्रस्ताव रखा। साथ ही बीकानेर और जैसलमेर में सौलर पार्क के निर्माण के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री कुमारी ने वर्तमान सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के प्रभाव का उल्लेख किया और कहा कि राज्य के आर्थिक आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांवों को शामिल किया जाएगा। हर घर में नल का पानी पहुंचाया जाएगा। इस पर 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। शहरों में पीने का पानी 2,300 करोड़ रुपये की लागत से उपलब्ध कराया जाएगा। बीकानेर और जैसलमेर में 2,950 करोड़ रुपये की लागत से नए सौलर पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे।

बजट 'विकसित राजस्थान 2047' के रोडमैप पर आधारित : शर्मा

बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बताए गए तीन मार्गदर्शक कर्तव्यों-तेज और स्थायी आर्थिक विकास, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण से प्रेरित है। शर्मा ने बताया कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 21,52,100 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 2023-24 से 41 प्रतिशत अधिक है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2026-27 का 6.10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को धरातल पर उतारने की कार्य योजना के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय पहली बार दो लाख रुपये से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता में कहा, आज हमने 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है, जो हमारे 'विकसित राजस्थान 2047' विजन दस्तावेज को वास्तविकता में बदलने की कार्य योजना है।

उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बताए गए तीन मार्गदर्शक कर्तव्यों-तेज और स्थायी आर्थिक विकास, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण से प्रेरित है। शर्मा ने बताया कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 21,52,100 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 2023-24 से 41 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि वहीं प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2,02,349 रुपये तक पहुंची है, जो 21.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। पूंजीगत व्यय 53,978 करोड़ रुपये रखा गया है, जो कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष से दोगुना है।

उन्होंने दावा किया कि संकल्प पत्र वर्ष 2023 की 392 घोषणाओं में से 282 पूरी हो चुकी हैं तथा बजट 2024-25 की 1,277 घोषणाओं में से 1,188 लागू की जा चुकी हैं और पिछले वर्ष की 1,441 घोषणाओं में से 1,246 को धरातल पर उतारा गया है। रोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं और निजी क्षेत्र में दो लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

उनके मुताबिक, वर्तमान में 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और एक लाख पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 76 लाख किसानों को 10,900 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं।

उनके मुताबिक, जल परियोजनाओं में शेखावाटी क्षेत्र तक यमुना जल लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपये , पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के लिए 26,000 रुपये करोड़ के कार्य आदेश तथा इंदिरा गांधी नहर और गंगनहर के लिए 4,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शर्मा ने कहा, ''स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो 53 प्रतिशत अधिक है। जे.के.लोन अस्पताल का विस्तार करते हुए यहां 500 बिस्तर का आईपीडी टॉवर बनाया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) में 200 बिस्तर की नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) वार्ड और पीडियाट्रिक सेंटर बनाया जाएगा।''

उनके मुताबिक, शिक्षा के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 23-24 के बजट से 35 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए 400 विद्यालयों को मुख्यमंत्री 'राजस्थान इनोवेशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन बजट के तहत 33,477 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 20.81 प्रतिशत अधिक है। शर्मा ने कहा कि इस वर्ष सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत समितियों पर नमो पार्क और 16 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई है तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबीजी रामजी) योजना में रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 10 बड़ी घोषणाएँ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 2026-27 के लिए इतिहास का सबसे बड़ा बजट छ21.52 लाख करोड़ पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 41% अधिक है। इस बजट में खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का मकसद सशक्त, समावेशी और विकासोन्मुख राजस्थान बनाना है।

1. बंपर नौकरियां

सरकार ने युवाओं के लिए 1 लाख नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। नियुक्ति प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। यह कदम बेरोजगारी कम करने और युवाओं को सरकारी नौकरी की सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2. स्वरोजगार लोन

राजस्थान के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार 1 लाख युवाओं को छ10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देने जा रही है। यह लोन नए उद्यमियों को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करेगा।

3. लखपति दीदी योजना

महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली 'लखपति दीदी' योजना में ऋण की सीमा छ1 लाख से बढ़ाकर छ1.5 लाख कर दी गई है। इससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे।

4. सड़क सुरक्षा में सुधार

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए जीवन रक्षक ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर चोटों को कम करना है।

5. मुफ्त इलाज

सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को और सुलभ बनाने के लिए ऐलान किया कि जन आधार या अन्य दस्तावेज न होने पर भी मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह नीति विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के लिए राहत साबित होगी।

6. नई टेस्टिंग एजेंसी

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए पेपर लीक रोकने हेतु 'राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' का गठन किया जाएगा। यह एजेंसी छ्ढ- मॉडल पर काम करेगी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

7. डिजिटल सुविधाओं का विस्तार

राजस्थान सरकार ने ई-मित्र की 100 सेवाओं को वॉट्सऐप पर उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसमें जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं शामिल हैं, जिससे जनता को डिजिटल सुविधा घर बैठे मिल सकेगी।

8. छात्रों को टैबलेट

10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में शामिल छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए छ20,000 का ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा।

9. पक्के घर

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सरकार ने ऐलान किया कि 2029 तक 28 लाख परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए जाएंगे। यह ग्रामीण विकास और जीवन स्तर सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

10. ऐतिहासिक बजट का महत्व

विशेषज्ञों के अनुसार यह बजट समावेशी और विकासोन्मुखी है। युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए स्वरोजगार, ग्रामीण परिवारों के लिए आवास और डिजिटल सेवाओं का विस्तार इसे राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी बजट बनाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं

बुजुर्ग मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा। जिनके पास जन आधार या डॉक्यूमेंट न हों, उन्हें भी सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलेगा। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लिए राहत है। फाइनेंशियल पैकेज और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य राजस्थान को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है।

बजट घोषणाओं से जनता की उम्मीदें धराशाही : सचिन पायलट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि बजट घोषणाओं से प्रदेश की जनता की उम्मीदें धराशाही हो गई हैं। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि जनता नाउम्मीद हो चुकी है कि बार बार घोषणाएं होती हैं, लेकिन बजट में उम्मीदें टूट जाती हैं। इस बजट में किसान, युवाओं और अन्य वर्गो को कुछ नहीं मिलने वाला है। आश्चर्य है कि सरकार ने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है, जबकि सरकार को इन योजनाओं को पूरा करने के लिए 35-40हजार करोड़ रुपए का लोन और लेना पड़ेगा, जो पहले की तुलना में डबल होगा। जब इंजन डबल है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और यंहा बात राजा प्रजा की हो रही है।

बजट में सत्ताधारी दल के सदस्यों की कई मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। बजट भाषण सुनने के बाद सरकार ने सिर्फ खानापूर्ति की है और अधिकांश योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। प्रदेश में परेशान किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग को यह सरकार कोई राहत नहीं दे पाई।

भारत यूएस डील पर पायलट ने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि यह डील दबाव में हुई है, वरना कौनसा देश किसी को दूसरे देश से सामान नही खरीदने के लिए प्रेशर कर सकता है। डील की जरूर है लेकिन इसकी डिटेल नही बता रहे हैं। पायलट ने कहा कि यह ट्रेड डील दबाव में हुई है और राहुल गांधी ने हमारे देश के हित में बात उठाई है।

राज्य सरकार का बजट निराशाजनक, विकास का रोडमैप नदारद : डोटासरा

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए किसी भी अपेक्षित नई योजना हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे प्रदेशवासियों में मायूसी व्याप्त है।

डोटासरा ने कहा कि बजट में एक बार फिर यमुना जल परियोजना का उल्लेख किया गया, लेकिन न तो इसके लिए कोई राशि आवंटित की गई और न ही यह स्पष्ट किया गया कि परियोजना कब शुरू होगी।

इसी तरह ईआरसीपी परियोजना में कराए जाने वाले कार्यों के लिए भी कोई बजट आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश की जमीन और लैंड बैंक के बंदरबाट को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे, वे बजट से सही साबित हो गए हैं। सरकार ने प्रतिदिन 8 उद्योगों को भूमि आवंटन की स्वीकृति देने की बात कही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वास्तव में कितने उद्योग स्थापित हुए, 'राइजिंग राजस्थान' के तहत कितना निवेश आया और कितने रोजगार सृजित हुए।

डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 3768 स्कूल भवन जर्जर हैं और कक्षा-कक्ष व शौचालयों में मरम्मत की आवश्यकता है, जिसके लिए करीब 21 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके बावजूद सरकार ने केवल 2500 विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपये और 300 भवन विहीन एवं जर्जर विद्यालयों के निर्माण के लिए मात्र 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह सार्वजनिक शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।

विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला सर्वस्पर्शी बजट : सीपी जोशी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार द्वारा वित्त मंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट को जनकल्याणकारी, विकासोन्मुखी एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्व सुखाय, सर्व हिताय की भावना के अनुरूप हर वर्ग का ध्यान रखने वाला सर्वस्पर्शी बजट है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि बजट में 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास, 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनाने, पेयजल परियोजनाओं के लिए 24 हजार करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी करने, एक साल में 3 लाख नए नल कनेक्शन जारी करने, 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने, 350 करोड़ की लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने, 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करवाने, सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री करने, चित्तौड़गढ़ में कुंभा पार्क डेवलप करने के लिए 31 करोड़ की घोषणा हुई है। सांसद सीपी जोशी ने कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को

जोड़कर सेंटर खोले जाने, एआई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने, प्रदेश के कॉलेजों में नए संकाय खोलने, सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज/अनुदान दिए जाने, जलवायु नीति और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ के निवेश का रोडमैप तैयार करने, लखपति दीदी योजना में कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख करने, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर रूरल वूमेन बीपीओ स्थापित करने, नमो नर्सरी खोलने, प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों- पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी और मंडावर के मुख्य प्रवेश मार्गों को मॉडल रोड के रूप में विकसित करने, डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खोलने जैसी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाओं से प्रदेश सुरक्षित होगा और विकास को रफ्तार मिलेगी।

युवा समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्र, समाज तथा शिक्षा के प्रति कर्तव्य को प्राथमिकता देने का युवाओं से आग्रह करते हुए बुधवार को कहा कि नौजवान अपने विकास के साथ राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें। बागड़े ने जगतपुरा में आयोजित राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को अधिकारों की बजाय राष्ट्र, समाज तथा शिक्षा के प्रति कर्तव्य की भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने राजस्थान को योद्धाओं की भूमि बताते हुए कहा, यहां का व्यक्ति शौर्य, वीरता और साहस से जुड़ा है। यहां निरंतर लड़ाइयां हुई लेकिन मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण की भावना रही है।

राज्यपाल ने स्काउट गाइड से संबंधित युवाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया और आपात स्थितियों में स्काउट गाइड की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। राज्य सरकार में मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि वह स्वयं स्काउट संगठन में रहे हैं। उनके मुताबिक, यह अनुशासन से जुड़ा युवाओं को प्रेरणा देने वाला संगठन है। स्काउट गाइड के राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य ने बताया कि अब तक जितनी भी राष्ट्रीय जंबूरियां हुई है, उन सभी में राजस्थान ने सर्वोच्च पदक प्राप्त करते हुए शिखर पर अपना स्थान बनाए रखा है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्र में लगभग 70 लाख स्काउट गाइड हैं, जिनमें से 18 लाख स्काउट गाइड के साथ राजस्थान सर्वोच्च स्थान रखता है।

राहुल गांधी के झूठे बयानों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अनुरोध करेंगे : रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी का भाषण ''झूठ से भरा'' था और सत्तारूढ़ गठबंधन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा किये गए ''झूठे'' दावों को सदन की कार्यवाही से हटाये जाने का अनुरोध करेगा।

केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल के भाषण के तुरंत बाद, रीजीजू ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य आसन को एक नोटिस देंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा बोले गए किसी भी कथन के प्रमाणीकरण की मांग की जाएगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''राहुल गांधी ने जो भी झूठ बोला है, हम उसे रिकॉर्ड से हटाए जाने की मांग करेंगे।'' हालांकि, राहुल गांधी ने अपने बयानों को प्रमाणित करने का वादा किया है, लेकिन मंत्री ने कहा, ''मुझे पता है कि वह उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने सदन में झूठ बोला है।'' रीजीजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अक्सर जानबूझकर झूठ बोलते हैं और फिर संबंधित मंत्री का जवाब सुनने के बजाय सदन छोड़कर चले जाते हैं।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के योग्य गंभीर स्वभाव वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, 2'हमारी पार्टी का रुख यह है कि हम राहुल गांधी के झूठ का जवाब सदन के बाहर देंगे, लेकिन सदन के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा।''

रीजीजू ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना नोटिस दिये पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर एक गंभीर आरोप लगाया है, जो विशेषाधिकार हनन है। उन्होंने कहा, ''हम आसन को आवश्यक सूचना देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर चर्चा में कोई उपयोगी और ठोस योगदान नहीं दिया, बल्कि केवल कुछ बेबुनियाद आरोप लगाए।'' संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को उस समय सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। उन्होंने कहा, ''भाषण देने के बाद वह (राहुल) तुरंत सदन से बाहर चले गए। जबकि नियम यह है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण दे दे, तो वह तुरंत सदन नहीं छोड़ सकता।''

उप्र बजट 2026-27 : अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के मद में 13 प्रतिशत की वृद्धि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए 2026-27 के बजट में आधारभूत ढांचा एवं औद्योगिक विकास के मद में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि की है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए सदन में कहा कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। अवस्थापना विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार की प्राथमिकताओं में है और इस दिशा में सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना हेतु 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट एवं स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया जारी है और इसके लिए 2374 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वहीं अटल अवसंरचना मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और फॉर्च्यून 500' कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 2023 की प्रोत्साहन नीति को लागू करने हेतु 1,000 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था है। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा औद्योगिक

गलियारे के अंतर्गत 200 रक्षा इकाइयों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें 35,280 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश और 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए 3822 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं जो 2025-26 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र एक नई योजना है जिसके लिए 575 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

खन्ना ने बताया कि एक नई योजना एक जिला-एक व्यंजन' के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हथकरघा वस्त्र उद्योग में लगभग 5041 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना से अधिक है। मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

अनुराग ठाकुर का राहुल पर पलटवार

जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेने के तुरंत बाद राहुल गांधी के सदन से चले जाने को लेकर उनपर निशाना साधते हुए कहा कि ''जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं।'' ठाकुर ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, पहले यह होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी सदन से चले जाते थे, लेकिन अब तो यह स्थिति हो गई है कि वह पहले ही भाग जाते हैं।

उन्होंने कहा, ''क्योंकि जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। ना उनके आरोप कभी टिक पाए, न ये नेता कभी टिक पाए हैं।'' भाजपा सांसद ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो भारत के लिए गर्व की और मुस्कुराने की बात है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि राहुल गांधी पिछली बार कब मुस्कुराये थे। वह पिछली बार 31 जुलाई 2025 को चार बजकर 20 मिनट पर

मुस्कुराये थे। जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया था। किसी ने भारत को तल्खी में डेड इकोनॉमी (मृत अर्थव्यवस्था)' कह दिया था...।''

उन्होंने जोर देते हुए कहा, ''भारत डेड इकोनॉमी नहीं, बल्कि डोमिनेटिंग (दबदबा रखने वाली) इकोनॉमी है।'' उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर राहुल पर पलटवार करते हुए कहा, ''मुझे तो लगता है कि इनकी प्रोग्रामिंग अंकल सैम (अमेरिका सरकार) और अंकल सोरोस (विवादों में रहे जॉर्ज सोरोस अमेरिकी निवेशक) ने की है। इनमें अंकल सैम का सिम कार्ड और अंकल सोरोस का सिम कार्ड है। उधर से टाइप होता है और इधर से टेलीकास्ट होता है।''

गौरव गोगोई के 'पाकिस्तान से संबंधों' पर एसआईटी की रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी : हिमंत विश्व शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई के कथित 'पाकिस्तान संबंधों' पर विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट को आगे की विस्तृत जांच के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

शर्मा ने कहा कि इससे पहले सांसद द्वारा हाल ही में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में किए गए 'खुलासों' को शामिल करने के लिए रिपोर्ट में संशोधन किया जाएगा, जिसमें रावलपिंडी जिले की उनकी यात्रा भी शामिल है। इसके बाद ही रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस सांसद का पड़ोसी देश से कथित संबंध चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी विधानसभा चुनाव

जीतने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संघर्ष यह सुनिश्चित करना है कि ''पाकिस्तान असम में प्रवेश न करे।'' शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में गोगोई द्वारा संवाददाता सम्मेलन में दिए गए बयानों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाएगा।

गोगोई ने दो नई जानकारियां प्रकट कीं - एक तो यह कि उनकी पत्नी सीधे पाकिस्तान से वेतन लेती थीं, और दूसरी यह कि उन्होंने रावलपिंडी जिले का दौरा किया था, जहां पाकिस्तान सेना का मुख्यालय है, लेकिन वीजा में इसका उल्लेख नहीं किया था।'' उन्होंने कहा, ''इन सभी जानकारियों को एसआईटी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा तथा कल या परसों दिल्ली भेज दिया जाएगा।''

राज्य सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में कथित हस्तक्षेप की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। अली तौकीर शेख के बारे में दावा किया जाता है कि उनकी गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से निकटता थी।

असम के मंत्रिमंडल ने मामले और एसआईटी रिपोर्ट को आगे की विस्तृत जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। गोगोई ने खुद और पत्नी पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जब उनसे पूछा गया कि केंद्र इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएगा, तो शर्मा ने कहा कि 'जब पाकिस्तान शामिल हो तो कोई भी मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा' और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 'बोलने से अधिक काम करने में विश्वास रखते हैं'।

विवादित वीडियो को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया : मुख्यमंत्री हिमंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि पुलिस ने कांग्रेस नेताओं की शिकायत के आधार पर एक विवादित वीडियो के संबंध में मामला दर्ज किया है। यह वीडियो प्रदेश भाजपा द्वारा अपलोड किया गया था और बाद में इसको हटा दिया गया था। शर्मा ने कहा कि एक भाजपा कार्यकर्ता ने भी इसी मुद्दे पर अलग से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब हटाए जा चुके वीडियो में शर्मा कथित तौर पर राइफल से दो लोगों पर निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखाई दिए थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने टोपी पहन रखी थी और दूसरा व्यक्ति दाढ़ी वाला था। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, ''बिल्कुल करीब से चलाई गई गोली।'' कृत्रिम मेधा (एआई) द्वारा निर्मित यह वीडियो शनिवार शाम प्रदेश भाजपा के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर अपलोड किया गया था, लेकिन राजनीतिक विरोध के बाद इसे हटा दिया गया।

शर्मा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''कांग्रेस ने मामला दर्ज कराया था और इसे दर्ज कर लिया गया है।'' कांग्रेस विधायक सिबामोनी बोरा और दिगंता बर्मन ने मंगलवार को यहां दिसपुर थाने में प्रदेश भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शर्मा ने दावा किया कि भाजपा के एक सदस्य ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा एक पार्टी के रूप में और वह स्वयं एक इंसान के रूप में, असमिया मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध किसी भी बात का समर्थन नहीं करते। शर्मा ने कहा, ''हम असमिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेशी मुसलमानों, मिया मुसलमानों के खिलाफ हैं। उस तस्वीर (वीडियो में) से बांग्लादेशी और भारतीय मुसलमानों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए था।''

सांसद द्वारा 'नीट, जेईई के कोचिंग माफिया' के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों की कथित मनमानी के खिलाफ बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार से इस 'कोचिंग माफिया' पर अंकुश लगाने की मांग की। महाराष्ट्र के भंडारा गोदिया से लोकसभा सदस्य पडोले ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भी लिखा है।

उन्होंने संसद भवन के मकर द्वार के निकट सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी की। पडोले ने अपने हाथ में तख्ती ले रखी थी, जिस पर कॉलेज खाली, कोचिंग मालामाल, माफिया पर 'कार्रवाई करो' लिखा था। पडोले कहा, ''आज नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं के नाम पर एक संगठित कोचिंग माफिया खड़ा हो चुका है, जिसने कॉलेजों को खाली और कोचिंग संस्थानों को करोड़ों रुपये का धंधा बना दिया है। ये कोचिंग संस्थान अभिभावकों से लाखों रुपये वसूल रहे हैं। मध्यम वर्ग और गरीब परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर्ज में डूब रहे हैं। तनाव, मानसिक दबाव और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''शिक्षा को व्यापार बनने से रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।''

जन प्रतिनिधि काम न करे तो मतदाताओं के पास उसे वापस बुलाने का अधिकार हो : राघव चड्ढा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने काम नहीं करने की स्थिति में जन प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को दिए जाने, प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुए बड़े हादसों और अभिभावकों की वृद्धावस्था में देखभाल न किए जाने जैसे मुद्दे उठाए तथा सरकार से अपेक्षित कदम उठाने का अनुरोध किया। शून्यकाल में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि जिस तरह मतदाताओं को मतदान का अधिकार है उसी तरह, काम नहीं करने की स्थिति में राइट टू रिकॉल' (जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार) भी मतदाताओं के पास होना चाहिए।

चड्ढा ने कहा ''अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को चुन सकता है तो उसे उन्हें काम न करने पर हटाने का हक भी होना चाहिए। 'राइट टू रिकॉल' व्यवस्था मतदाताओं को

अधिकार संपन्न बनाएगी ताकि अगर जन प्रतिनिधि काम न करे तो उसे हटाया जा सके।'' उन्होंने कहा कि ''सांसद या विधायक चुने जाने के बाद अगर जन प्रतिनिधि काम न करे तो जनता के पास पांच साल तक बर्दाश्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। गलत नेता को चुनने के एक गलत फैसले से पूरा क्षेत्र, पूरा समय बर्बाद होता है और लाखों मतदाता इसका खामियाजा भुगतते हैं।''

चड्ढा ने स्पष्ट किया कि 'राइट टू रिकॉल' नेताओं के खिलाफ हथियार नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल' के तहत मतदाता एक निर्धारित और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।

रामपुर सीआरपीएफ शिविर आतंकी हमला : न्यायालय उप्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 2007 के रामपुर सीआरपीएफ शिविर' आतंकी हमले के मामले में चार आरोपियों को दी गई मौत की सजा और एक अन्य को दी गई आजीवन कारावास की सजा निरस्त कर दी गयी थी। रामपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर 31 दिसंबर 2007 की रात को हुए हमले में सीआरपीएफ के आठ जवान मारे गए थे और पांच घायल हो गए थे।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किये और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की।

पांचों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एम एस खान पेश हुए। राज्य सरकार ने पिछले साल 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें इस मामले में चार लोगों को मृत्युदंड और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का निर्माण शुरू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रेजिनगर/भाषा। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज यहां बहुचर्चित मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया। हाल ही में जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) का गठन करने वाले कबीर ने घोषणा की कि बेलडांगा के रेजिनगर में इस मस्जिद का निर्माण दो साल के भीतर पूरा हो जाएगा और इसकी लागत लगभग 50-55 करोड़ रुपये आयेगी।

सैकड़ों लोगों के उत्साह के बीच, निर्माण श्रमिकों ने दोपहर के आसपास इमारत के लिए ईंटे रखने का समारोह शुरू किया। कबीर ने कहा कि कई पक्षों के विरोध के बावजूद मस्जिद का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। निर्माण कार्य में भागीदारी दर्शाने के लिए कई समर्थक अपने सिर पर ईंटें ढोते हुए देखे गए।

जेयूपी प्रमुख ने कहा, विरोध करने वालों से मैं कहना चाहूंगा कि वे हट जाएं। लोगों को अपने-अपने धर्मों का पालन करने तथा मंदिर, गिरजाघर या जो चाहें बनाने की पूरी आजादी है। मैं इस्लाम के नाम पर किसी का विरोध नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य अल्लाह को प्रसन्न करना और अपनी धार्मिक आस्था को निभाना है, किसी पर कुछ थोपना नहीं। उन्होंने कहा, ''इस मस्जिद के निर्माण को रोकने वाली धरती पर कोई ताकत नहीं है। अल्लाह की कृपा से हम दो साल के भीतर इसका निर्माण पूरा कर लेंगे। इसे बनाने में 50-55 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।'' कबीर ने घोषणा की कि बोर्ड परीक्षाएं होने के चलते वह फिलहाल निर्धारित 'बाबरी यात्रा' - नादिया के पलाशी से उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार तक 235 किलोमीटर की रैली को स्थगित रखेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, वह बृहस्पतिवार को पलाशी से बेलडांगा तक 22 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। कबीर ने पिछले साल छह दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखी थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर उठाए गए इस कदम से पश्चिम बंगाल में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आयीं। खबरों के मुताबिक उन्होंने पहले दो दिनों में ही 28 लाख रुपये से अधिक का चंदा जुटाया था। भरतपुर से तृणमूल विधायक को कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। कबीर ने आज यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों को टक्कर देगी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जरिए कृषि क्षेत्र के लिये संकट पैदा कर रही भाजपा सरकार : अखिलेश यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को भारत के किसानों और गरीबों के लिए नुकसानदेह बताते हुए बुधवार को कहा कि सबसे दुख की बात यह है कि सरकार सबसे ज्यादा आबादी को रोजी-रोटी देने वाले कृषि क्षेत्र के लिये संकट पैदा कर रही है। यादव ने यहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानमंडल में प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए बुलायी गयी प्रेस वार्ता में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को देश के किसानों और गरीबों के लिये घातक बताया। उन्होंने कहा, ''अमेरिका से व्यापार समझौते के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चोट और सबसे पहले चोट अगर किसी को लगने जा रही है तो हमारे किसानों और गरीबों को लगने जा रही है। यह सबसे दुख की बात

है भारत में सबसे ज्यादा आबादी जिस खेती पर निर्भर है, सरकार उसी पर संकट पैदा कर रही है।''

यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''जो खबरें सुनने को मिल रही हैं उनके अनुसार बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद भारत में भेजे जाएंगे। अगर हम अमेरिका को 500 अरब डॉलर का कारोबार देंगे तो 'मेक इन इंडिया' का क्या होगा? हमारा कृषि क्षेत्र, जिस पर 60 से 70 प्रतिशत गरीब आबादी निर्भर करती है, उसका क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को हटाने के लिए 'वोट की चोट' देने के साथ-साथ सड़क पर आना होगा तथा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सपा प्रमुख ने पूछा कि आखिर सरकार इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं कर रही कि कौन-कौन से उत्पाद भारत के बाजार में लाए जाएंगे। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करके भारत मां को बेच देने के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोप के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सपा प्रमुख ने कहा, ''यह बहुत गंभीर बात इसलिए भी है कि अमेरिका से संबंध भी हों और हम अपना बाजार भी उनके हवाले ना करें। हमने बहुत बड़े पैमाने पर चीन को अपना बाजार दे दिया। भाजपा ने हमारी पूरी विदेश नीति उलझाकर रख दी है। आज हमने पूरा बाजार किसी और के हाथ में दे दिया इसलिए भारत को किस दिशा में जाना है, यह भारत की जनता को सोचना पड़ेगा।''

सुविचार

खुश रहा करो क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

डीपफेकः नकली दुनिया के असली खतरे

केंद्र सरकार ने डीपफेक पर लगाम लगाने और एआई से तैयार सामग्री के प्रबंधन के संबंध में ऑनलाइन मंचों के लिए जो नियम बनाए हैं, वे झूठ के प्रसार पर पाबंदी लगाने में काफी मददगार साबित होंगे। हालांकि इन नियमों से चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएंगी। एआई के विस्तार के साथ डीपफेक के स्वरूप बदलते जाएंगे। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनसे सावधान रहना होगा। वर्तमान में सोशल मीडिया पर एआई द्वारा निर्मित अनगिनत फेक वीडियो मौजूद हैं। उन पर कई लोगों ने भरोसा किया है। एक चैनल पर ग्रामीण परिवेश के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। उनमें एक युवती दिखाई देती है, जिसे सैकड़ों युवक प्रेम प्रस्ताव और विवाह प्रस्ताव भेज चुके हैं। हकीकत यह है कि इस दुनिया में उस युवती का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह एआई द्वारा निर्मित है। उसका चैनल पाकिस्तान से संचालित किया जाता है। 'युवती' को प्रस्ताव भेजने वाले ज्यादातर लोग भारतीय हैं। सोचिए, क्या आईएसआई ऐसे लोगों को हनीट्रैप के जरिए शिकार बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती? इसी तरह सोशल मीडिया मंच पर एक पेज है। उस पर लोगों को जल्द धनवान बनाने का दावा किया जाता है। घर बैठे, बिना मेहनत किए, मामूली निवेश से लाखों रुपए कमाने के सपने दिखाए जाते हैं। जो व्यक्ति इस 'निवेश योजना' का लाभ उठाना चाहता है, उससे जरूरी दस्तावेज मांगे जाते हैं। लोग बिना सोचे-समझे दस्तावेज भेज देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि पेज पर बताई गईं सारी योजनाएं फर्जी हैं और उनके निर्माण में एआई की मदद ली गई है। अगर किसी दिन खबर मिले कि उन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सैकड़ों लोगों से वित्तीय धोखाधड़ी की गई है तो इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

अगर एआई का इस्तेमाल शिक्षाप्रद, उपयोगी और ज्ञानवर्द्धक सामग्री बनाने में हो तो उसका स्वागत है। कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं। उनके प्रयासों को सराहना मिल रही है। वहीं, कई वीडियो भ्रांतियां फैला रहे हैं। एक चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो की मानें तो भैंस पहाड़ से कूदेगी तो उड़ेगी! ऐसे वीडियो किशोर ज्यादा देखते हैं। उनके मन में जिज्ञासा होती है। अगर वह वीडियो देखकर कोई बच्चा अपने घर की छत पर चुपचाप जाए और उड़ान भरने की कोशिश में गलत कदम उठा ले तो क्या होगा? एआई का गलत इस्तेमाल किसी देश में बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है। शत्रु एजेंसियां ऐसे मौके की ताक में रहती हैं। याद करें, 'ऑपरेशन सिंदूर' की शुरुआत के कुछ ही दिन बाद भारतीय वायुसेना की एक अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में गलत दावे किए जा रहे थे। उन पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ भारतीय नागरिक सरकार की रणनीति पर सवाल उठाने लगे थे। हकीकत यह थी कि वह वीडियो फर्जी था। एआई की मदद से ऐसे कई वीडियो बनाए गए थे। उन सबमें झूठे दावे किए गए थे। ये वीडियो नागरिकों में डर और अविश्वास की भावना पैदा करते हैं। सोचिए, भविष्य में भारत सरकार पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे और सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी वीडियो की बौछार होने लगे तो उन्हें देखकर लोगों के मनोबल पर क्या असर होगा? एआई शुरुआती दौर में है। अपराधियों ने अभी से इसके जरिए उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। पांच-दस साल बाद जब यह तकनीक ज्यादा उन्नत हो जाएगी, तब अपराधों का ग्राफ किस रफ्तार से ऊपर जाएगा? भारतीय एजेंसियों को इन बदलावों पर कड़ी नजर रखनी होगी। उन्हें चार कदम आगे रहना होगा, ताकि अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब न हो पाएं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ डिजिटल सुरक्षा को भी मजबूत बनाना होगा।

ट्वीटर टॉक

प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और आर्थिक सुदृढ़ता को केंद्र में रखते हुए महिला सशक्तिकरण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी एवं ग्रामीण विकास तथा मजबूत आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता देने वाला वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया।

-दिया कुमारी

विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला ऐतिहासिक बजट! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्पष्ट विजन के साथ हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर घर में खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

-भजनलाल शर्मा

मा. वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा आज उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत बजट (वित्तीय वर्ष 2026-27) सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम तथा तकनीकी निवेश से समृद्ध होते 'नए उत्तर प्रदेश' की जीवंत झांकी है।

-योगी आदित्यनाथ

प्रेरक प्रसंग

ज्ञान-कर्म से सम्मान

प्राचीन चीन में कन्फ्यूशियस अपने संतुलित, व्यावहारिक और सहज ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक झील के किनारे बैठा दुखी होकर रो रहा था। कन्फ्यूशियस उसके पास गए और पूछा, 'क्या तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हुआ है?' युवक बोला, 'गुरुजी, मैं एक छोटे पद पर काम करता हूं। लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैं जितनी मेहनत करता हूं, उतना ही उपहास मिलता है। मैं सम्मान चाहता हूं, पर उसे पाने का मार्ग नहीं समझता।' कन्फ्यूशियस शांत होकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने लकड़ी से मिट्टी पर एक वृत्त बनाया और बोले, 'देखो, यह वृत्त समाज है बड़ा, विस्तृत और विविध।' फिर बीच में एक छोटा-सा बिंदु बनाकर बोले, 'और यह तुम हो, अपनी जगह छोटा, पर अपूर्ण नहीं।' युवक ने पूछा, 'तो सम्मान कैसे मिलेगा?' कन्फ्यूशियस ने मिट्टी पर धीरे से रेखाएं खींचना शुरू किया। बिंदु से बाहर की ओर, वृत्त को छूने तक। वे बोले, 'सम्मान मांगने से नहीं, फैलने से मिलता है। जब तुम्हारा ज्ञान, धैर्य और कर्म बाहर की ओर बढ़ते हैं, तब समाज स्वयं तुम्हें पहचानता है।'

सामयिक

जनरल नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा और दिल्ली पुलिस की जांच

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पीडीएफ कॉपी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रसार को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला किसी अपराध या घोटाले से जुड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मकथा से संबंधित है जो अभी औपचारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई और फिर भी व्यापक रूप से पढ़ी जा रही है। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की डिजिटल प्रति अचानक विभिन्न संदेश माध्यमों और सामाजिक मंचों पर फैल गई। देखते ही देखते यह रचना केवल सैन्य इतिहास की किताब न रहकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। प्रश्न यह नहीं रह गया कि पुस्तक लीक कैसे हुई, बल्कि यह बन गया कि वह अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी।

यह आत्मकथा चार दशकों से अधिक लंबे सैन्य जीवन का विवरण देती है। एक युवा अधिकारी के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती से लेकर देश की थलसेना के सर्वोच्च पद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। इसमें पूर्वी सीमा पर हुए टकराव, पश्चिमी मोर्चे पर तनाव, पड़ोसी देशों के साथ संघर्षविराम, और एक भीषण वैश्विक महामारी के दौरान सेना की भूमिका जैसे प्रसंग शामिल हैं। ऐसे समय में जब देश का सैन्य इतिहास अक्सर आधिकारिक वक्तव्यों और संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रह जाता है, यह पुस्तक घटनाओं के भीतर झांकने का अवसर देती है। शायद यही कारण है कि इसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। प्रकाशन की प्रक्रिया सामान्य नहीं रही। पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, अग्रिम आदेश भी लिए गए, परंतु अचानक सब कुछ रोक दिया गया। पाठकों को धन वापस कर दिया गया और कहा गया कि आवश्यक स्वीकृतियां लंबित हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखी जाने वाली स्मृतियों के लिए रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, यह कोई नई बात नहीं है। परंतु जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों से यह सामने आया कि उसी अवधि में दर्जनों अन्य पुस्तकों को अनुमति मिल चुकी है और केवल यही एक रचना अटकी हुई है, तो संदेह स्वाभाविक हो जाता है।

लेखक स्वयं कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया था और उसे प्रकाशक को सौंप दिया था। अनुमति प्राप्त करना उनका दायित्व नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुस्तक की सामग्री उनकी अपनी लिखी हुई है और उसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी नहीं है। यही नहीं, पुस्तक के मसौदे को पहले ही कई वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने पढ़ा था और उसकी सराहना भी की थी। इन प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि सामग्री न तो मनगढ़ंत है और न ही हल्की। इसके बावजूद पुस्तक पर चुप्पी बनी रही। इस बीच कुछ समाचार माध्यमों ने इसके अंशों के आधार पर लेख प्रकाशित किए। उन लेखों में सीमा पर हुए संकटों के दौरान लिए गए राजनीतिक और सैन्य निर्णयों का उल्लेख था। संसद में जब इन संदर्भों का उपयोग करने की कोशिश की गई तो भारी हंगामा हुआ और चर्चा रोक दी गई। इसके तुरंत बाद वही डिजिटल प्रति, जिसे अब तक केवल सीमित लोगों ने देखा था, व्यापक रूप से फैलने लगी। यह एक अजीब स्थिति थी, जिसमें एक पुस्तक आधिकारिक रूप से अस्तित्वहीन मानी जा रही थी, परंतु वास्तविकता में हजारों पाठकों तक पहुंच चुकी थी।

अब जांच का केंद्र यह है कि इस अनधिकृत प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है। कानून की दृष्टि से यह कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अप्रकाशित सामग्री को बिना अनुमति साझा किया गया। यदि यह माना जाए कि पुस्तक में संवेदनशील सैन्य जानकारियां हैं, तो उस पर गोपनीयता से जुड़े कानून भी लागू हो सकते हैं। परंतु यहां एक गहरा प्रश्न छिपा है। क्या जांच का उद्देश्य वास्तव में कानून का पालन कराना है या फिर उन तथ्यों

को नियंत्रित करना है जो असुविधाजनक साबित हो सकते हैं। इस आत्मकथा में जिन घटनाओं का उल्लेख है, वे हाल के वर्षों की सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय घटनाओं में से हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई झड़पों में देश ने अपने जवान खोए, परंतु उन घटनाओं के बारे में आधिकारिक विवरण सीमित रहा। सरकार की ओर से एक विशेष प्रकार का आख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें दृढ़ता और सफलता पर जोर था। यदि किसी पूर्व थलसेना प्रमुख की पुस्तक उस आख्यान से अलग तस्वीर पेश करती है, तो स्वाभाविक है कि वह राजनीतिक रूप से असहज कर सकती है। परंतु क्या असहजता ही किसी रचना को रोकने का पर्याप्त कारण हो सकती है।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ केवल सामान्य नागरिकों तक सीमित नहीं है। जिन लोगों ने राज्य की सर्वोच्च जिम्मेदारियां निभाई हैं, उनका अनुभव और दृष्टिकोण भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर विषय है और किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रकाशन सावधानी से होना चाहिए। परंतु सुरक्षा और सेंसरशिप के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। जब सुरक्षा के नाम पर हर असुविधाजनक प्रश्न को दबाया जाने लगे, तब वह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में न तो लेखक ने अपनी बात से पीछे हटने का प्रयास किया और न ही प्रकाशक ने यह कहा कि सामग्री गलत है। प्रकाशक ने केवल इतना कहा कि पुस्तक अभी सार्वजनिक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या सामग्री में नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक होने में है। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को और गहरा बनाता है।

डिजिटल युग में किसी रचना को पूरी तरह रोक पाना लगभग असंभव है। एक बार यदि वह किसी रूप में बाहर आ गई, तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि प्रतिबंध और देरी कभी-कभी विपरीत प्रभाव डालते हैं। जिस पुस्तक को कुछ कार्यालयी फाइलों में दबाकर रखा गया था, वह अब कहीं अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है, वह भी बिना किसी आधिकारिक संदर्भ और विमर्श के। इससे गलत व्याख्याओं और अफवाहों की संभावना भी बढ़ जाती है। अंततः यह प्रश्न बना रहता है कि समाधान क्या है। क्या बेहतर यह नहीं होता कि पुस्तक को आवश्यक संपादन और स्पष्ट चेतावनियों के साथ प्रकाशित होने दिया जाता, ताकि पाठक उसे पूरे संदर्भ में समझ सकें। जांच और प्रतिबंध के रास्ते ने न केवल लेखक और प्रकाशक को असमंजस में डाला है, बल्कि पाठकों को भी अधूरी और असंतुलित जानकारी के भरोसे छोड़ दिया है।

यह प्रकरण केवल एक आत्मकथा का नहीं है। यह उस बड़े संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें राज्य की शक्ति और नागरिक समाज की जिज्ञासा आमने-सामने खड़ी होती हैं। इतिहास बताता है कि सत्य को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। वह कभी दस्तावेज के रूप में, कभी स्मृति के रूप में और कभी डिजिटल प्रति के रूप में सामने आ ही जाता है। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम उसे खुली बहस और परिपक्व संवाद के साथ स्वीकार करेंगे या डर और नियंत्रण के माध्यम से उसे और रहस्यमय बना देंगे। जनरल नरवणे की आत्मकथा आज भले ही औपचारिक रूप से प्रकाशित न हो, परंतु उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि कहानियां केवल अनुमति से नहीं, आवश्यकता से जीवित रहती हैं।

चिंतन

धर्म, समाज और राष्ट्र की चेतना जगाने वाले स्वामी दयानंद

योगेश कुमार गोयल

मोबाइल : 9416740584.

आर्य समाज के संस्थापक के रूप में वंदनीय महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में 12 फरवरी 1824 को हुआ था और 12 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाएगी। स्वामी दयानंद ऐसे देशभक्त, समाज सुधारक, मार्गदशक और आधुनिक भारत के महान चिंतक थे, जिन्होंने न केवल ब्रिटिश सत्ता से जमकर लोहा लिया बल्कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान की। 1857 की क्रांति में उनका अमूल्य योगदान था। स्वामी दयानंद का बचपन बहुत अच्छा बीता लेकिन उनके जीवन में घटी एक घटना ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि वे 21 वर्ष की आयु में ही अपना घर बार छोड़कर आत्मिक एवं धार्मिक सत्य की तलाश में निकल पड़े और एक सन्यासी बन गए। जीवन में ज्ञान की तलाश में वे स्वामी विरजानंद से मिले, जिन्हें अपना गुरु मानकर उन्होंने मथुरा में वैदिक तथा योग शास्त्रों के साथ ज्ञान की प्राप्ति की। 1845 से 1869 तक कुल 25 वर्षों की अपनी वैराग्य यात्रा में उन्होंने कई प्रकार के दैविक क्रियाकलापों के बीच विभिन्न प्रकार के योगों का भी गहन अभ्यास किया।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी दयानंद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और 'स्वराज' का नारा उन्होंने ही दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने अपनाया और 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा दिया। वेदों का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ उनकी महत्ता लोगों तक पहुंचाने तथा समझाने के लिए उन्होंने देशभर में भ्रमण किया। जीवनपर्यन्त वेदों, उपनिषदों का पाठ करने वाले स्वामी जी ने पूरी दुनिया को इस ज्ञान से लाभान्वित किया। उनकी किताब 'सत्यार्थ प्रकाश' आज भी दुनियाभर में अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित हो रही है। वेदों को सर्वोच्च मानने वाले स्वामी दयानन्द ने वेदों का प्रमाण देते हुए हिन्दू समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का डटकर विरोध किया। जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में उनका योगदान उल्लेखनीय है, इसीलिए उन्हें 'सन्यासी योद्धा' भी कहा जाता है। दलित उद्धार तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने कई आन्दोलन किए। हिन्दू धर्म

के अलावा इस्लाम तथा ईसाई धर्म में फैली बुराईयों और अंधविश्वासों का भी उन्होंने जोरदार खंडन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण, धार्मिक कुरीतियों की रोकथाम तथा वैश्विक एकता के प्रति समर्पित कर दिया। वे आध्यात्मिक क्रांति के संदेशवाहक थे।

स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुम्बई के गिरगांव में गुड़ी पड़वा के दिन 10 अप्रैल 1875 को की थी, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के साथ समूचे विश्व को एक साथ जोड़ना था। आर्य समाज के द्वारा उन्होंने दस मूल्य सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी। मूर्ति पूजा के अलावा वे जाति विवाह, महिलाओं के प्रति असमानता की भावना, मांस के सेवन, पशुओं की बलि देने, मंदिरों में चढ़ावा देने इत्यादि के सख्त खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने लोगों में जागरुकता पैदा करने के अथक प्रयास किए। स्वामी दयानंद हिन्दी भाषा के प्रबल समर्थक थे और उनका मत था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक ही भाषा 'हिन्दी' बोली जानी चाहिए। मानव शरीर को नश्वर बताते हुए वह कहते थे कि हमें इस शरीर के जरिये केवल एक अवसर मिला है, स्वयं को साबित करने का कि मनुष्यता' और आत्मविवेक' क्या है। वे कहा करते थे कि शक्ति किसी अलौकिकता या चमत्कारिता के प्रदर्शन के लिए नहीं होती। सभी धर्मों और उनके अनुयायियों को वे एक ही ध्वज तले बैठा देखना चाहते थे। दरअसल उनका मानना था कि आपसी लड़ाई का फायदा सदैव तीसरा उठाता हैं, इसलिए इस भेद को दूर करना आवश्यक है। कर्म करने को लेकर स्वामी जी तर्क देते थे कि काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। वह कहा करते थे कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और तब आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौटकर आएगा। उनका कहना था कि अज्ञानी होना गलत नहीं है लेकिन अज्ञानी बने रहना गलत है।

नजरिया

साहस और विनम्रता जीवन की सच्ची महक

संजीव ठाकुर

मोबाइल 9009415415

जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता के लिए मनुष्य को निरंतर कर्म की प्रधानता रखकर संयम तथा मनोबल भी रखना होगा। इसके अलावा मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास ना होकर उस पर नियंत्रण रख स्वामी बनने का प्रयास करना होगा तब सोची गई सफलता आपके सामने होगी। कठिन तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अपने मनोबल को सदैव विनम्रता, संयम और साहस के साथ ऊंचा रखना चाहिए। अपने द्वारा की गई मेहनत पर विश्वास एवं निरंतरता रखनी होगी। तब जाकर ही जीवन में सफलता के पल आपके सामने आएंगे। निराशा, हताशा और हीन भावना को कठोर श्रम के बलबूते पर ही विजय प्राप्त की जा सकती है।

जीवन में उतार-चढ़ाव, कठिन समय और विषम परिस्थितियां आती ही रहती हैं। संकट का समय विषम परिस्थितियां जीवन के अलग-अलग पहलू हैं। इनसे जूझ कर जो मानव आगे बढ़ता है, वह उच्च मनोबल वाला साहसी व्यक्ति होता है। व्यक्ति के जीवन में साहस, उच्च मनोबल ही सफलता की कुंजी है। जिस भी व्यक्ति ने विषमताओं में रास्ता निकलने का साहस करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है वही सफल हुआ है। हमेशा सफलता का मूल आत्मविश्वास, कठिन श्रम और उच्च आदर्श वाले व्यक्ति की प्रेरणा ही सफलता दिलाने वाली होती है।

मनुष्य को कभी भी किसी परिस्थिति में मन से हार नहीं माननी चाहिए। उसे सदैव प्रयासरत रहकर परिश्रम तथा जुझारू पन से हर परिस्थिति का सामना कर सदैव अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी हर हार, हर पराजय से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए एवं इससे अनुभव प्राप्त कर फिर से खड़ा होने एवं उस पराजित मनोदशा से छुटकारा पाकर फिर से लड़ने की ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, यह सफलता का बड़ा मंत्र है। सर्वप्रथम मनुष्य अपने मनोबल से किन्हीं भी परिस्थितियों को जीतने का साहस रखता है, इसीलिए मनोबल मनुष्य की पहली आवश्यकता है। मनोबल ही साहस को जन्म देता है और साहस, आत्मबल को और आत्मबल से ही मनुष्य किन्हीं भी परिस्थितियों से जूझना एवं टकराने की क्षमता पैदा करता है। जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ ना हो तो वह निश्चिंत होकर साहस, क्षमता एवं संयम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है की पीछे पलट कर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, शिवाय आगे बढ़ने एवं सफलता के लिए अग्रसर होने के। मनुष्य का मनोबल एवं दृढ़ प्रतिज्ञा ही मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। मनुष्य के जीवन का एक तथ्य और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है सकारात्मक सोच, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की ओर उत्साहित करती रहती है। सकारात्मक सोच एवं किसी भी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने की सुनियोजित योजना मनुष्य में आशाओं को भर देती है एवं परिस्थितियों को चुनौती देने की क्षमता का विकास करती है। यह मनुष्य ही है जो हर परिस्थिति में साहस और मनोबल के दम पर उससे विजय प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन और पशु के जीवन में यही फर्क है कि मनुष्य के पास सोचने के लिए मस्तिष्क होता है और वह उसके सकारात्मक उपयोग के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। मनुष्य मुस्कुराता, हंसता और खिलखिलाता है। जबकि पशु में मुस्कुराने हंसने की क्षमता नहीं होती, और यही कारण है कि मनुष्य ने विषम परिस्थितियों पर सदैव विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है, वह काफी हद तक सफलता पाने में सफल भी हुआ है। मनुष्य यदि परिस्थितियों में अन्य प्रतियोगिताओं में, खेल में, या युद्ध में पराजित होकर भी प्रेरणा लेकर पुनः साहस के साथ पुनःतैयार होता है तो वह आने वाले समय में सफलता का सही हकदार भी होता है, क्योंकि उसने पूरी क्षमता, साहस ,मनोबल के साथ पराजय को स्वीकार कर के उससे कुछ सीखने का प्रयास किया है। अपनी कमियों को दूर करने की हर संभव कोशिश भी की है ।इस तरह वह अगली परीक्षा में जरूर सफल होता है और यही मानव जीवन का सफल अध्याय भी होता है। कुल मिलाकर परिस्थितियां तथा घटनाएं ,दुर्घटनाएं मनुष्य को परिस्थितियों के सामने पराजित करने, झुकाने की कोशिश करती हैं किंतु मानव अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक एवं मानसिक आत्मबल से उसे सफलता में बदल देता है। अनवरत प्रयासरत व्यक्ति अपने साहस परिश्रम से हर चुनौतियों का सामना कर परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर अपने जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों से जूझ कर जो मानव सदैव सफल होता है वह पूरे समुदाय और समाज के लिए एक प्रेरणादाई व्यक्तित्व बन कर पूरे समाज एवं देश को मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को किन्हीं भी परिस्थितियों में, खासकर विषम परिस्थितियों में अपने मनोबल और साहस को त्यागना नहीं चाहिए। उच्च मनोबल और साहस की ऊर्जा ही मनुष्य को नई दिशा, नए प्रकाश पुंज की ओर अग्रसर करती है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति को 14 सप्ताह की सजा

सिंगापुर/भाषा। सिंगापुर की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और एक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के आरोप में 14 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह जानकारी प्राप्त हुई। चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) की रिपोर्ट के अनुसार, 36 वर्षीय विकनेस्वरन वी मोगनावल ने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के अधिनियम के तहत एक आरोप और एक लोक सेवक के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के दूसरे आरोप में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली है। वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसके पड़ोसी के बच्चे अक्सर उसके अपार्टमेंट के पास वाले साझा गलियारे में खेलते थे। उसकी पड़ोसी अपने पति, तीन बच्चों, सास, बहन और एक नौकरानी के साथ वहीं रहती थी। उन्होंने इससे पहले सामुदायिक पुलिस इकाई से शोर की समस्या के बारे में शिकायत की थी।

शुरुआत में स्थिति में सुधार हुआ लेकिन पिछले वर्ष दिवाली के मौके पर जब बच्चे वहां खेल रहे थे तो वह उनके शोरगुल से नाराज हो गया। उसने कहा कि दिवाली उसका त्योहार है और बच्चों के वहां खेलने के कारण उसे अपने घर पर आयोजित एक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। विकनेस्वरन को पता था कि उसकी पड़ोसी और उसका परिवार मलय-मुस्लिम हैं और इस्लाम में सूअर का मांस खाना वर्जित है। गुस्से में आकर उसने सूअर के मांस का एक डिब्बा खोला और उसे गलियारे के फर्श पर फैला दिया ताकि जब उसके पड़ोसी वहां से गुजरें तो उन्हें सूअर का मांस दिखाई दे।

उस दिन रात करीब 10:15 बजे उसने पुलिस को फोन किया और कहा कि उसका मन कर रहा है कि वह अपने पड़ोसी के घर पर सूअर का मांस फेंक दे।

दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 2025 में रिकॉर्ड 9.52 करोड़ यात्रियों ने किया सफर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, 2025 में भी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 2025 में रिकॉर्ड 9.52 करोड़ यात्रियों ने इसके टर्मिनल से सफर किया, जो अमीरात की जारी आर्थिक तेजी को दर्शाता है। वैश्विक महामारी के बाद के वर्ष में हवाई अड्डे की गतिविधियों में तेज उछाल आया है। इसे वैश्विक यात्रा रुचि के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सबसे बड़े शहर दुबई में बढ़ते पर्यटन, व्यापार एवं रियल एस्टेट अवसरों से बल मिला है। दुबई में पिछले साल पर्यटकों की संख्या पांच प्रतिशत बढ़कर 1.96 करोड़ तक पहुंच गई। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र का हवाई अड्डा लंबी दूरी की विमानन कंपनी एमिरेट्स का केंद्र है जो अमीरात में 'दुबई इंक.' के नाम से जानी जाने वाली सरकारी व सरकार से जुड़ी कंपनियों के नेटवर्क को मजबूती देता है।

दुबई एयरपोर्ट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पॉल ग्रिफिथ्स ने कहा कि 2025 में दुबई अंतरराष्ट्रीय ने यह दिखा दिया, ''रिकॉर्ड यातायात अब कोई अपवाद नहीं बल्कि इसकी संचालन वास्तविकता का हिस्सा बन चुका है।'' दुबई हवाई अड्डे से 2024 में 9.23 करोड़ यात्रियों ने सफर किया था जबकि 2023 में यह आंकड़ा 8.69 करोड़ रहा। 2019 में वैश्विक महामारी से ठीक पहले यात्रियों की संख्या 8.63 करोड़ रही थी और 2018 में 8.91 करोड़ थी। दुबई अंतरराष्ट्रीय से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए भारत शीर्ष गंतव्य रहा जहां 1.19 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की।

इसके बाद सऊदी अरब (75 लाख) और ब्रिटेन (63 लाख) का स्थान रहा। इस हवाई अड्डे से 108 विमानन कंपनियां 110 देशों के 291 शहरों के लिए उड़ानें संचालित करती हैं।

प्रदर्शन

भारतीय किसान परिषद के किसानों और बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्थानीय लोगों ने बुधवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 2.5 लाख लोगों को प्रभावित करने वाली लंबी बिजली कटौती के खिलाफ सेक्टर 16 में चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

हनुमान जी की जन्मस्थली पहुंचे चंकी पांडे, विशेष पूजा-अर्चना की

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता चंकी पांडे अपने मजाकिया अंदाज को लेकर दर्शकों के बीच खास पहचान रखते हैं। हाल ही में अभिनेता ने रामभक्त हनुमान की जन्मस्थली के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा सदस्य साक्षी महाराज से मुलाकात की। चंकी पांडे ने इस पवित्र यात्रा की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कीं। तस्वीरों में चंकी मंदिर में पूजा करते नजर आ रहे हैं।

कुछ फोटोज में वे पंडित जी के साथ नजर आ रहे हैं, तो एक में वे साक्षी महाराज के साथ पोज देते हुए भी दिख रहे हैं। अभिनेता ने लिखा, जय हनुमान जी। नाशिक के अंजनेरी पहाड़ियों के पास स्थित हनुमान जी मंदिर में सुंदर दर्शन हुए। यह हनुमान जी की जन्मस्थली है। अभिनेता के पोस्ट शेयर करने के बाद उनके फैंस और इंडस्ट्री के कई लोगों ने कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी। रामभक्त हनुमान की जन्मस्थली महाराष्ट्री के नासिक जिले में स्थित अंजेरी पहाड़ियों के पास स्थित है। यह जगह हनुमान भगवान की जन्मस्थली मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर माता अंजना ने पवनपुत्र को जन्म दिया था।

'सूबेदार' फिल्म का टीजर रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

69 वर्ष की आयु में भी दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर दर्शकों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी लगभग हर फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्रेम और समर्थन मिलता है। हाल ही में फिल्म 'वॉर-2' में दमदार एक्शन के बाद अब अनिल कपूर अपनी नई फिल्म 'सूबेदार' में भी जबरदस्त एक्शन और गंभीर अंदाज में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनका सशक्त और प्रभावशाली लुक उन्हें नई पीढ़ी के अभिनेताओं के बीच भी अलग पहचान देता दिखाई दे रहा है। अनिल कपूर की आगामी फिल्म 'सूबेदार' का टीजर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म 5 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

एक्शन और ड्रामा से भरी 'सूबेदार' कई भावनाओं और पारिवारिक-सामाजिक परेशानियों से जूझते एक शख्स की कहानी है, जो सैनिक होते हुए भी जिंदगी में आई चुनौतियों से लड़ने के लिए पूरी जान लगा देता है। 'सूबेदार' अर्जुन मौर्य की कहानी है जो एक आम नागरिक के रूप में जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, अपनी बेटी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते को संभालते हैं और सामाजिक कुप्रथाओं का सामना करते हैं। कभी देश के लिए लड़ने वाले सैनिक रहे सूबेदार को अब अपने घर और परिवार की रक्षा के लिए अपने कई दुश्मनों से लड़ना होगा।

1 मिनट से ज्यादा के टीजर में अभिनेता का राउडी लुक दिखाया गया है। 69 की उम्र में चश्मा लगाए, दुश्मनों को धूल चटाते अनिल कपूर कमाल लग रहे हैं। फिल्म 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली है और टीजर के रिलीज के साथ फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ चुका है।

अनिल कपूर के लिए फिल्म 'सूबेदार' खास है क्योंकि बीते साल उन्होंने अपने जन्मदिन पर पोस्ट रिलीज के साथ फिल्म के बारे में पहली बार जानकारी दी थी। अभिनेता का कहना था कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन को नहीं दिखाती, बल्कि एक परिवार के संघर्ष और चुनौतियों को पेश करती है। ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में होने वाली है।

बता दें कि फिल्म में बतौर लीड भूमिका निभाने के अलावा अभिनेता ने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म की कहानी सुरेश त्रिवेणी और प्रज्वल चंद्रशेखर ने लिखी है, जबकि डायरेक्शन सुरेश त्रिवेणी ने किया है।

रणवीर सिंह के बाद सलमान खान के करीबी को मिली धमकी, मांगे करोड़ों रुपए

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड में एक बार फिर अपराधियों की धमकियां बढ़ गई हैं। हाल ही में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद बुधवार को अभिनेता रणवीर सिंह को भी व्हाट्सएप के जरिए धमकी मिली। अब खबर आ रही है कि सलमान खान के करीबी को भी धमकी दी गई है।

साथ ही करोड़ों रुपयों की मांग भी की गई है। सलमान खान के बेहद करीबी व्यक्ति को धमकी भरा ईमेल मिला है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है और करोड़ों रुपये की वसूली की मांग की है। धमकी देने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का होने का भी दावा किया है। पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।

मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी है, जिसके अनुसार, यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। धमकी में पैसे न देने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, अभी तक सलमान खान या उनके करीबी की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और एहतियातन सतर्कता बरत रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक, बिश्नोई गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों के आसपास ट्रेस हुई है। गैंग ने रेकी का काम अपने अलग-अलग गुर्गों को सौंपा था।

पुलिस इन सुरागों को इकट्ठा कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। यह घटना रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के महज कुछ दिनों बाद सामने आई है, जिससे बॉलीवुड में दहशत का माहौल है। सलमान खान पहले से ही बिश्नोई गैंग की धमकियों का सामना कर रहे हैं। गैंग ने उनके घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी। अब उनके करीबी को निशाना बनाया गया है।वहीं, पुलिस का मानना है कि ये धमकियां मुख्य रूप से वसूली के लिए दी जा रही हैं।

रिंग में उतरीं फातिमा सना शेख, दिखाया फुल पावर अवतार

मुंबई/एजेन्सी

बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री फातिमा सना शेख अपनी फिल्मों और सोशल मीडिया पोस्ट से दर्शकों का खास ध्यान खींचती हैं। उन्होंने मंगलवार को एक मजेदार पोस्ट किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में वे बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए नजर आ रही हैं, जबकि कुछ में वे रिंग के अंदर आत्मविश्वास से भरे पोज देती दिख रही हैं। उनका पूरा लुक काफी पावरफुल और एनर्जेटिक लग रहा है, लेकिन अभिनेत्री की आखिरी स्लाइड काफी मजेदार है, जिसमें उन्होंने बॉक्सिंग के महान खिलाड़ी अमेरिका के प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली की एक आइकॉनिक तस्वीर लगाई है। अभिनेत्री ने लिखा, तितली की तरह हल्के रहो, और मधुमक्खी की तरह वार करो, मुहम्मद। फातिम ने अपनी इस पोस्ट के जरिए न सिर्फ अपनी फिटनेस को दर्शाया है बल्कि मोहम्मद अली के इंस्पिरेशन कोट्स को भी दिखाया है। अभिनेत्री का पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे कयास लगा रहे हैं कि आने वाली फिल्म में शायद वे बॉक्सिंग की भूमिका में होंगी।

1997 में फिल्म 'चाची 420' में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली फातिमा सना ने बॉलीवुड में कई यादगार फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'लूडो', 'अजीब दास्तां', और 'सैम बहादुर' शामिल हैं। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर ऐसे पोस्ट शेयर करती हैं, जो मोटिवेशनल और मजेदार होते हैं। फातिमा इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जिसका खुलासा जल्द ही होगा। इससे पहले वे विजय वर्मा के साथ फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आई थीं। फिल्म में दोनों के अलावा, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी भी अहम रोल में थे। फिल्म को लेकर दर्शकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। हालांकि, शुरुआत में फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी क्रेज देखा गया था।

बातचीत

अभिनेता शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी अपनी आने वाली फिल्म 'ओ' रोमियो ' का प्रमोशन करते हुए फैंस से बातचीत करते हुए।

'अस्सी' का नया गाना मन हवा रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री तापसी पन्नू की आगामी फिल्म अस्सी जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यह एक कोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। सोमवार को फिल्म के निर्माताओं ने नया गाना 'मन हवा' रिलीज कर दिया। यह गाना दिल को छूने वाला और जोश भरने वाला है, जो फिल्म की तेज-तर्रार जांच और कोर्ट ड्रामा की भावना को बखूबी से पेश करता है। फिल्म में मुश्किल सवाल उठाने की हिम्मत और सच के लिए लड़ने की ताकत को यह गाना अच्छे से बयां करता है। सॉन्ग 'मन हवा' को मोहित चौहान, परंपरा टंडन और रोचक कोहली ने मिलकर गाया है और रोचक कोहली ने इसका संगीत तैयार किया है। यह गाना डर के बजाय हिम्मत, चुप्पी के बजाय सच और समझौते के बजाय पक्के इरादे को चुनने की बात करता है। यह धीरे-धीरे दिल को सुकून देता है और अंदर से ताकत जगाता है, ताकि मुश्किल हालात में भी खुद के लिए और अपने विश्वास के लिए लड़ सको। गाने को लेकर मोहिक चौहान ने अपने विचार व्यक्त किए।

उन्होंने कहा, मुझे ऐसे गाने पसंद हैं जो कोई कहानी सुनाते हैं और कुछ कहने की ताकत रखते हैं। गाना 'मन हव' शुरू से ही मुझे ईमानदार लगा और इसे रिकॉर्ड करते समय, मैंने गाने को फील किया और कहानी को खुल के जीने दिया।

'थप्पड़' और 'मुल्क' जैसी फिल्में देने के बाद एक बार फिर अनुभव सिन्हा ने कोर्ट ड्रामा फिल्म 'अस्सी' का निर्देशन किया है।

गाने को लेकर अनुभव का कहना है कि यह गाना इस फिल्म की भावनात्मक धड़कन है। उन्होंने कहा, 'मन हवा' सिर्फ गाना नहीं बल्कि, पूरी फिल्म की धड़कन है। एक ऐसी कहानी में जो सच्चाइयों को चुनौती देती है और मुश्किलों का सामना करती है, यह ट्रैक बोलने, उठने और सभी मुश्किलों के सामने मजबूती से खड़े होने की हिम्मत को दिखाता है। यह उस ताकत का जश्न मनाता है जो हमारे अंदर मौजूद होती है और जब हम ईमानदारी और मजबूती के साथ दुनिया का सामना करने का फैसला करते हैं।

अनुभव सिन्हा की इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा, कानी कुसृति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, जीशान अय्यूब, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, और सीमा पाहवा समेत कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण टी-सीरीज कर रहा है। फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बदल गई है 'हंगामा' की अंजलि, फिल्में छोड़ रियल एस्टेट एजेंट बन कमा रही पैसा

मुंबई/एजेन्सी

साल 2003 में रिलीज हुई हास्य फिल्म 'हंगामा' आज भी दर्शकों के जेहन में ताजा है। कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म ने दर्शकों को शुरुआत से अंत तक ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी, उसके किरदार भी उतने ही खास थे। हर पात्र की अपनी अलग दुनिया थी, लेकिन सभी किरदार एक-दूसरे से बखूबी जुड़े हुए थे। यही आपसी उलझनें और गलतफहमियां फिल्म को एक मजेदार मोड़ देती रहीं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपनी अदायगी से दर्शकों का दिल जीता। खासकर भोली-भाली अंजलि का किरदार, जिसने अपनी सादगी और मासूमियत से लोगों को खूब प्रभावित किया। इस भूमिका को अभिनेत्री रिमी सेन ने निभाया था। हालांकि, लंबे समय से रिमी सेन बड़े पर्दे से दूर हैं। अभिनय की दुनिया से दूरी बनाने के बाद अब वह रियल एस्टेट के क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक एजेंट के रूप में काम कर रही हैं।

फिल्म 'हंगामा' में नंदू और अंजलि की लव स्टोरी और सभी किरदारों की कॉमेडी ने हर बार दर्शकों का दिल जीता। फिल्म को जितनी बार देखा गया, उतनी बार दर्शक खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। फिल्म में अंजलि का किरदार

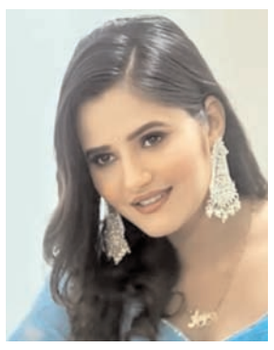

निभाने वाली रिमी सेन की भूमिका ने भी दर्शकों का दिल जीता, लेकिन हंगामा की रिमी सेन आज असल जिंदगी में बहुत बदल चुकी हैं। अभिनेत्री का चेहरा पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि फिलर्स और बोटॉक्स ट्रीटमेंट की वजह से चेहरे की बनावट पहले जैसी नहीं रही है।

यूजर्स भी अभिनेत्री के चेहरे को देखकर हैरान हैं और हर पोस्ट पर यही सवाल कर रहे हैं कि चेहरे का क्या ही करा डाला! फिल्मों से दूर रिमी सेन इन दिनों दुबई बेस्ड रियल एस्टेट एजेंट बन गई है। अभिनेत्री रियल एस्टेट के व्यवसाय में जानी-मानी हस्ती बन चुकी हैं और लोगों को उनके सपनों का घर दिलवाने में भी मदद करती हैं। रिमी का इंस्टाग्राम रियल एस्टेट इवेंटस की वीडियो से भरा है और सिर्फ दुबई ही नहीं, वे बाकी शहरों में भी अपना बिजनेस सेटअप करने का प्लान बना रही हैं। भले ही हिंदी सिनेमा की पारी ज्यादा लंबी नहीं रही, लेकिन पर्दे से दूर होने के बाद उन्होंने दूसरी फील्ड में अपना सिक्का जमा लिया है।

रियल एस्टेट के अलावा रिमी प्राइवेट ब्रांड इवेंट्स का भी हिस्सा बनती हैं और बड़े ब्रांड्स के लॉन्च में भी पहुंचती हैं। सोशल मीडिया पर रिमी को 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और वे अभिनेत्री के नए अवतार से हैरान भी हैं। फिल्मों की बात करें तो अभिनेत्री ने बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं की फिल्मों में काम किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें 'धून' और 'हंगामा' जैसी फिल्मों से पहचान मिली थी।

'स्काईबैग्स' बना चेन्नई सुपर किंग्स का ऑफिशियल लगेज पार्टनर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। लगेज और बैकपैक रेंज के लिए मशहूर 'स्काईबैग्स' ने वर्ष 2026 सीज़न के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ ऑफिशियल लगेज पार्टनर के तौर पर साझेदारी की घोषणा की है ।स्काईबैग्स ने इस साझेदारी के साथ खेलों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है इस साझेदारी के तहत स्काईबैग्स चेन्नई सुपरकिंग्स की ब्रांड पहचान के अनुसार तैयार किए गए एक्सक्लूसिव को-ब्रांडेड लगेज और बैकपैक की रेंज को बाजार में पेश करेगा। इस साझेदारी के बाद स्काईबैग्स-2026 सीज़न में सीएसके के फैन्स से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेगा।इसयहां आयोजित एक कार्यक्रम में वीआईपी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अतुल जैन ने कहा कि क्रिकेट भारत की संस्कृति में रचा-बसा है और सीएसके इस क्रिकेट लीग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और कामयाब फ्रेंचाइजी में से एक है। यह साझेदारी स्काईबैग्स की उस सोच का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसके तहत ब्रांड भारत के युवा और बड़े सपने देखने वाले लोगों को पसंद आने वाले प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनसे जुडने का प्रयास करेगी।उन्होंने कहा कि सीएसके को सच्ची लगन, लगातार बेहतर प्रदर्शन और होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है जो हमारे ब्रांड की सोच के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि स्काईबैग्स के लिए यह खेल जगत के साथ जुड़ाव की शुरुआत है और आने वाले समय में इस तरह की साझेदारियां और देखने को मिलेंगी। कार्यक्रम में चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के एस विश्वनाथन ने कहा कि चेन्नई सुपरकिंग्स की फैमिली में स्काईबैग्स को आधिकारिक लगेज पार्टनर के तौर पर स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।उन्होंने कहा कि हमने अपने फैन्स के लिए सीएसके के प्रति अपना प्यार और जोश दिखाने का एक नया तरीका पेश किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस साझेदारी के बाद हमारे फैन्स को और बेहतर अनुभव मिलेगा, साथ ही टीम के समर्थकों के साथ हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत एवं दृढ़ होगा।

कर्नाटक इनरवियर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी समिति की हुई घोषणा

महावीरचन्द बने अध्यक्ष, कृष्णमूर्ति बने सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक इनरवियर एसोसिएशन की वर्ष 2026-28 की नई कार्यकारिणी समिति की घोषणा नए अध्यक्ष महावीरचन्द मेहता की अध्यक्षता में की गई। नई कमेटी में अश्विन सेमलानी को उपाध्यक्ष, गौरव शर्मा को उपाध्यक्ष, जी. कृष्णमूर्ति को सचिव, सूरज शर्मा को सहसचिव, राजेश चोपड़ा को कोषाध्यक्ष व विनोद चौहान को सहकोषाध्यक्ष, मूलसिंह राजपुरोहित को सदस्यता अभियान मंत्री, माधुराम, श्रीपाल मेहता व भरत जैन को कानून मंत्री बनाया गया।

इसके अलावा सेंकी जैन, मनीष जैन, अमित जैन , विक्रम दास, घेवरचंद , मिश्रीलाल को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया है। पूर्व अध्यक्ष दिलीप जैन की उपस्थिति में इस नई कार्यकारिणी टीम की औपचारिक घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों को साथ लेकर उद्योग के विकास, व्यापारिक हितों की रक्षा एवं संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। नए अध्यक्ष महावीरचन्द मेहता ने पूरी टीम को उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया।

अरिहंत पीयू कॉलेज ग्लोबल कैम्पस में मनाया गया 'सम्प्रीति' विदाई समारोह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। अरिहंत पीयू कॉलेज द्वारा ग्लोबल कैंपस में द्वितीय पीयूसी के विद्यार्थियों के लिए 'सम्प्रीति' नामक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाणी विलास कॉलेज के प्राचार्य और केएसईएबी के वरिष्ठ सहायक निदेशक एमआर प्रसन्ना कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रबंध ट्रस्टी यशस्वी नागोरी ने अध्यक्षीय संबोधन देते हुए विद्यार्थियों को अपने भविष्य के प्रयासों में मूल्यों, अनुशासन और दृढ़ता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस समारोह में विद्यार्थी संचालन विभाग के प्रमुख और सहयोगी विवेक गुप्ता, अरिहंत डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार, पीयूसी प्राचार्य महेश आरबी उपस्थित थे। सभी अतिथियों व पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के अनुशासन, समर्पण और दृढ़ निश्चय के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के समापन पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। पीयूसी द्वितीय के विद्यार्थियों को सांस्कृतिक व प्रेरणात्मक समापन कार्यक्रम के साथ विदाई दी गई।

नेलमंगला में फाल्गुन होली उत्सव 1 मार्च को

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । स्थानीय बाबा भक्तों द्वारा एक मार्च को नेलमंगला स्थित छोटा वृंदावन में सुबह 10 बजे से फाल्गुन व होली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

आयोजकों ने बताया कि इस मौके पर गायिका मनीषा तुलस्यान भजनों की प्रस्तुति देंगी। सुबह 10 बजे ज्योत प्रज्वलन के बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

कलश स्थापना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के मारेनहल्ली में मुनेश्वरा स्वामी देवालय में गोपुरा कलश स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महेंद्र मुणोत उपस्थित थे। मुणोत ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं अन्नदान कार्यक्रम में सेवा प्रदान की। आयोजकों ने अतिथियों को सम्मानित किया।

निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 72 लोग हुए लाभान्वित

चेन्नई/दक्षिण भारत। स्थानीय अविशा स्माइल्स डेंटल क्लिनिक में बुधवार को निशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। यह शिविर प्रकाशचंद अनोपचंद के स्मृति में और अग्रवाल आई हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया। इस शिविर का संपूर्ण लाभ अरविंद कुमार, जयाबेन परिवार ने लिया।

इस शिविर में 72 लोगों ने आंखों की निशुल्क जांच कराई। 18 लोगों को चश्मे दिए जाएंगे और 3 चयनीत लोगों की निशुल्क मोतियाबिंदु सर्जरी कराई जाएगी।

स्वागत

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मेयर वी.वी. राजेश के नेतृत्व में केरल के प्रतिनिधिमंडल और तिरुवनंतपुरम नगर निगम के नए चुने गए भाजपा पार्षदों का 'विकास केरलम' के लिए आगमन पर स्वागत किया।

कनाडा के एक स्कूल और मकान में गोलीबारी; संदिग्ध समेत 10 लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वैंकूवर (कनाडा)/एपी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना में हमलावर सहित आठ लोगों की मौत हो गई तथा एक मकान में दो और लोग मृत पाए गए जिनका संबंध इस घटना से माना जा रहा है। कनाडाई प्राधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 'रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस' (आरसीएमपी) ने बताया कि टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में हुई गोलीबारी में 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। कनाडा में स्कूल में गोलीबारी की घटनाएं होना दुर्लभ हैं।

लगभग 2,400 लोगों की आबादी वाला टंबलर रिज शहर वैंकूवर से 1,000 किलोमीटर उत्तर में अल्बर्टा की सीमा के पास स्थित है। प्रांतीय सरकार की वेबसाइट के अनुसार, टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में सातवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 175 छात्र पढ़ते हैं। आरसीएमपी के अधीक्षक केन फ्लॉयड ने पत्रकारों को बताया कि जांचकर्ताओं ने हमलावर की पहचान कर ली है, लेकिन उसका नाम जारी नहीं किया। न ही यह स्पष्ट है कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया।

फ्लॉयड ने कहा, ''हम अभी इस बात को समझने की स्थिति में नहीं हैं कि इस त्रासदी का कारण क्या था।'' उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि पीड़ितों और आरोपी के बीच क्या संबंध थे। आरसीएमपी ने एक बयान में कहा, ''गोलीबारी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के दौरान पुलिस ने खतरे का पता लगाने के लिए स्कूल में प्रवेश किया। तलाशी के दौरान अधिकारियों को कई पीड़ित मिले। संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया, जिसके शरीर पर खुद को चोट पहुंचाने के निशान दिखायी दे रहे थे।''

बयान में कहा गया है, ''संदिग्ध को छोड़कर छह अन्य व्यक्तियों को स्कूल के भीतर मृत पाया गया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया है। तीसरे व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गयी।'' 'पीस रिवर साउथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट' ने मंगलवार को कहा कि सेकेंडरी स्कूल और टंबलर रिज एलिमेंटरी स्कूल दोनों में ''लॉकडाउन'' लागू किया गया है यानी किसी को अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

बेंगलूरु में फैशन की चमक बिखेरेगी हाई लाइफ

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। मशहूर फैशन प्रदर्शनी हाई लाइफ एक बार फिर बेंगलूरु में अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है। इसका आयोजन 13 फरवरी से द ललित अशोक में होगा। यह 15 फरवरी तक जारी रहेगी। आयोजकों ने बताया कि हाई लाइफ प्रदर्शनी डिज़ाइनर फैशन, आकर्षक ज्वेलरी, लग्ज़री एक्सेसरीज़ और ट्रेंड-फ़ॉरवर्ड लाइफस्टाइल कलेक्शन के एक्सक्लुसिव शोकेस के साथ आ रही है। उन्होंने कहा कि इसमें अनूठे क्यूरेटेड लेबल्स, स्टेटमेंट स्टाइल्स और क्लासिक एलिगेंस का शानदार मेल देखने को मिलेगा। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो यादगार शॉपिंग अनुभव पसंद करते हैं। हाई लाइफ प्रदर्शनी फैशन प्रेमियों के लिए एक ऐसा मौका है, जहां वे लेटेस्ट ट्रेंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी वार्डरोब को अपडेट कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी में फैशन से रूबरू होने और उसे महसूस करने का मौका मिलेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था, 10 विमान मार गिराए गए थे : ट्रंप ने दोहराया दावा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन/भाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को शुल्क (टैरिफ) के जरिए रोक दिया था जो उनके अनुसार परमाणु युद्ध में बदल सकता था।

ट्रंप ने मंगलवार को 'फॉक्स बिजनेस' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ''मैंने आठ युद्ध रुकवाए। इन आठ युद्धों में से कम से कम छह शुल्क के कारण सुलझे। मैंने कहा कि अगर आप यह युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर शुल्क लगा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं।''

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ''और उन्होंने कहा, इसका इससे क्या लेना-देना?' मैंने कहा, आप पर शुल्क लगाया जाएगा।' जैसे भारत और पाकिस्तान। मेरे विचार में यह एक परमाणु युद्ध में बदल सकता था। वे वास्तव में युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, 10 विमान मार गिराए गए थे।''

ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमें लड़ाई रोकने के लिए राजी करके कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने कहा, ''मेरे विचार में वे परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। शुल्क के बिना युद्ध रुकवाना संभव नहीं होता।''

ट्रंप ने पिछले साल 10 मई से लेकर अब तक कई बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा किया है। उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद दोनों पड़ोसी देशों ने सैन्य टकराव को ''पूर्ण और तत्काल'' रोकने पर सहमति जताई। भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है।

भारत ने पिछले साल सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

न्यायालय ने गलत बाल काटने पर मुआवजा राशि घटाकर 25 लाख रु. की

अदालत ने माना कि दस्तावेजों की फोटोकॉपी का मूल्यांकन करते समय, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने का फैसला देने में गलती की।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के सैलून में गलत बाल काटने'' पर एक महिला को दी जाने वाली मुआवजा राशि को दो करोड़ रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने छह फरवरी को व्यवस्था दी कि बेशक सेवा में खामी सिद्ध हो चुकी है, फिर भी उपभोक्ता विवादों में मुआवजा केवल ठोस साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए न कि शिकायतकर्ता की महज मांग या हठ पर। न्यायमूर्ति बिंदल ने 34 पृष्ठों में लिखे फैसले में कहा, ''क्षतिपूर्ति केवल शिकायतकर्ता की धारणाओं या हठ पर नहीं दी जा सकती। खासकर जब दावा करोड़ों रुपये का हो, तो मुआवजा देने के लिए कुछ विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश करना जरूरी है।'' फैसले में कहा गया कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जहां राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग किसी छोटे मुद्दे पर विचार कर रहा हो और मुआवजा केवल सामान्य नियम या अनुमान के आधार पर दिया जा सके।इसने कहा, ''मुआवजे का दावा करोड़ों रुपये का था, जिसके लिए यह साबित करना आवश्यक था कि सेवा में कमी के कारण प्रतिवादी को कुछ आर्थिक नुकसान हुआ। इसे केवल दस्तावेजों की फोटोकॉपी पेश करके साबित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर पेश की गई फोटोकॉपी में उन विसंगतियों को ध्यान में रखा गया है जिनके बारे में अपीलकर्ता द्वारा बताया गया...इसलिए, पुनर्विचार के बाद भी प्रतिवादी इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए कोई ठोस आधार साबित नहीं कर पाया है।''

अदालत ने माना कि दस्तावेजों की फोटोकॉपी का मूल्यांकन करते समय, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने का फैसला देने में गलती की। आदेश में कहा गया, आयोग का यह तर्क कि प्रतिवादी को हुए मानसिक आघात के कारण उसने मूल दस्तावेज नहीं रखे होंगे और इसलिए फोटोकॉपी पर भरोसा किया जा सकता है, इतनी बड़ी रकम देने के लिए पर्याप्त नहीं है।'' इसने कहा कि अगर फोटोकॉपी प्रस्तुत भी कर दी जाए, तो भी उस आधार पर किए गए दावे को सही ठहराने के अन्य तरीके मौजूद हैं। न्यायालय ने कहा, ''भले ही दीवानी प्रक्रिया संहिता सख्ती से लागू न हो, लेकिन आयोग ने यह आकलन नहीं किया है कि प्रतिवादी को दो करोड़ रुपये का नुकसान भला कैसे हुआ।

विवादित फैसले में की गई सामान्य चर्चा इसे उचित नहीं ठहरा सकती।'' अप्रैल 2018 में प्रबंधन पेशेवर अशना रॉय दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के सैलून गई थीं। रॉय ने आरोप लगाया कि हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके कहने के विपरित बाल छोटे काट दिए, जिससे उन्हें मानसिक आघात लगा और करियर के अवसरों से हाथ धोना पड़ा। एनसीडीआरसी ने शुरू में उन्हें दो करोड़ रुपये दिए जाने का फैसला सुनाया था।

जम्मू कश्मीर में बहने वाली चंद्रा और भागा नदियों में सुरंग बनाने की राज्यसभा में उठी मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। जम्मू कश्मीर में बहने वाली चंद्रा और भागा नदियों में सुरंग बनाने की मांग करते हुए बुधवार को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि यह सुरंग बनने से सतलुज नदी में इन दोनों नदियों का पानी आएगा तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बहुत राहत मिलेगी। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए तिवाड़ी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे बड़ा प्रहार पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि को निलंबित कर किया। उन्होंने कहा कि 1960 में कराची में इस संधि पर पंडित जवाहर लाल नेहरू और अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए थे जिसके अनुसार पश्चिमी नदियां चेनाब, झेलम और सिंधु का 80 फीसदी पानी पाकिस्तान को दिया गया। तिवाड़ी ने कहा कि संधि के अनुसार पूर्वी नदियों सतलुज, रावी और व्यास का पानी हिन्दुस्तान को दिया गया।

तिवाड़ी ने कहा कि संधि के तहत भारत को केवल बीस फीसदी पानी मिला। उन्होंने कहा संधि के तहत, भारत को सिंधु नदी के कुल पानी का लगभग 20 फीसदी हिस्सा मिला। भारत को तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलुज का पूर्ण अधिकार मिला है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब का 80 फीसदी पानी मिला। है। भाजपा सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान में पंजाब और सिंध की पूरी सिंचाई होने के बाद से सिंधु, झेलम और चिनाब का 22 मिलियन एकड़ फुट (एमएएफ) पानी समुद्र में जाता रहा। यह पानी की बहुत अधिक मात्रा है। तिवाड़ी ने कहा कि संधि में हर तीन साल में इसके पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया था पर पाकिस्तान सहमत नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान सरकार को संधि के पुनरावलोकन के लिए दो बार पत्र लिखा था लेकिन पड़ोसी देश नहीं माना। उन्होंने कहा कि पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने संधि को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा यह केवल समुद्र में बह जाने वाले 22 एमएएफ पानी के लिए नहीं किया गया। तिवाड़ी ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में बहने वाली चंद्रा और भागा नदियों में सुरंग बना दी जाए तो इन नदियों का पानी सतलुज नदी में आ जाएगा।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.